साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

آوازِ تسنیم

tasneemtv.official@gmail.com

PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | वर्षः 02 / अंकः 16 | जयपुर, सोमवार, 02 नवंबर , 2026 | पृष्ठः 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन

मैं भारत के हर नागरिक और हर युवा से कह रहा हूं, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे : राहुल गांधी



आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को सही रास्ते पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना है। उन्होंने दावा किया- ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और वे जेल जाएंगे।

ज्ञानेश कुमार के बिना मोदी पीएम और शाह गृहमंत्री नहीं बनते

रामलीला मैदान में वोट बचाओ देश बचाओ नाम की इंडिया ब्लॉक मेगा रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरी बात सुनिए, मैं जो कहता हूं वह हमेशा सच साबित होता है। मैं भारत के हर नागरिक और युवा से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाएगा और वह जेल जाएंगे। उन्होंने सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया, अगर ज्ञानेश कुमार नहीं होते, तो न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह देश के गृहमंत्री बनते।

देश में सालों से हो रही है वोटों की चोरी, 2024 का चुनाव अवैध

राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश में सालों से वोटों की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा- सालों से इस देश में वोट चोरी होती आ रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में वोट चोरी हुई है। ईवीएम के जरिए और वोटर लिस्ट से नाम हटाकर और जोड़कर वोट चुराए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, 2024 के चुनाव के बाद भारत के 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव एक गैर-कानूनी चुनाव था। यह एक चोरी का चुनाव था। यह मैं नहीं कह रहा, यह चुनाव आयोग कह रहा है।

मोदी कहीं नहीं जाएगा नारे पर राहुल ने कसा तंज

भाजपा के मोदी कहीं नहीं जाएगा वाले नारे पर मज़ाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, मोदी कहीं नहीं जा सकते, अगर वह जाना भी चाहें, तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वोट चुराए हैं, इसलिए उनके, शाह और ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देश को इंसाफ मिलेगा।

राहुल ने कहा, मोदी, शाह, आरएसएस ने देश में नफ़रत फैलाई है, जिससे देश की आत्मा को नुकसान पहुंच रहा है। आज देश कह रहा है कि हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें प्यार और भाईचारा चाहिए, मोहब्बत का देश चाहिए। हम इसे जरूर पूरा करेंगे।

हमें शिव की बारात जैसा भारत पसंद

अपने भाषण में शिव की बारात का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा, शिव की बारात में कोई भी शामिल हो सकता है।

हर जीवित प्राणी इसका हिस्सा बन सकता है।

क्या किसी को इसमें शामिल होने से रोका जा सकता है? नहीं।

हम ऐसा ही भारत चाहते हैं। अगर कोई किसान कड़ी मेहनत करता है, तो उसे उसका फल मिलना चाहिए। अगर कोई छात्र 18 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसे रोजगार मिलना चाहिए। हम ऐसा देश नहीं चाहते जो सिर्फ दो या तीन लोगों का हो।

पांचवें टी20 में न्यूज़ीलैंड ने भारत को 7 विकेट से दी मात, सीफर्ट-फिलिप्स ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

आवाज़ ए तसनीम

हैमिल्टन। न्यूज़ीलैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत को 7 विकेट से मात दे दी। हालांकि ये सीरीज 3-2 से भारत के नाम रही।

हैमिल्टन में खेले गए पांचवें मैच में मेजबान टीम ने 192 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। जिसका पूरा

क्रेडिट टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स को जाता है।

सीफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि फिलिप्स 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे।

इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए। ये फिलिप्स का इस सीरीज में चौथा फिफ्टी प्लस स्कोर था।

इसके अलावा वो एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा 340 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था, जिन्होंने 331 रन बनाए थे। इससे पहले भारत इस सीरीज में पहली बार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरा, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों ओपनर अभिषेक और संजू चार ओवर के अंदर ही आउट हो गए।

लेकिन उसके बाद कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे भारत 191 रन तक पहुंच सका। अय्यर ने 23 गेंदों में 50 और किशन ने 32 गेंदों में 61 रन बनाए। आखिर में नमन धीर ने 33 और रेड्डी ने 22 रनों की पारी खेली।

न्यूजीलैंड की तरफ से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहें।

उन्होंने 4 ओवर में केवल 19 रन खर्च करके 4 विकेट झटके।

इसके अलावा टिकनर और स्मिथ को दो-दो विकेट मिले।

एडम मिल्ने को प्लेयर ऑफ द मैच और ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया।

मुख्यमंत्री का कायमखानी समाज के साथ किया संवाद

विकसित राजस्थान के निर्माण में हर समाज की भागीदारी जरूरीः भजनलाल शर्मा





आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा सोच, वरिष्ठजनों का अनुभव और मातृशक्ति की सहभागिता विकास की नई राह प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। ऐसे में समाज के प्रबुद्धजन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने और जरुरतमंद परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री रविवार को कायमखानी समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प के अनुरूप डबल इंजन सरकार समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

सरकार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

शिक्षा समाज की प्रगति का आधार

उन्होंने कहा कि शिक्षा और सामाजिक चेतना समाज की वास्तविक प्रगति का आधार हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार ने छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के मैस भत्ते को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया है।

वहीं, विभिन्न योजनाओं के तहत 26 हजार से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को 17 करोड़ 16 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 4 हजार 786 अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं।

गांव-गांव में अटल ज्ञान केन्द्र,युवा सपनों को दें उड़ान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र एवं ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। जिनके माध्यम से युवाओं को पढ़ने के लिए संबंधित आवश्यक सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से आयोजित करवा रही है। युवा मन लगाकर पढ़ें, डबल इंजन सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए साथ खड़ी है।

ऐतिहासिक जल समझौते उतर रहे धरातल पर

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। पानी से जुड़े 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हाथ में लिए गए हैं।

दशकों से लंबित रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल और किशाऊ समझौते सहित विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इससे पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए पानी मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा शेखावाटी क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला की पहचान शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन हवेलियों को पर्यटन से जोड़ने पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं, प्रदेश में बनाए जा रहे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे में से 3 शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े हैं। साथ ही, इस क्षेत्र से एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्र सेवा करने वालों का सरकार कर रही सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन-पेंशनर सैनिकों की आर्थिक सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है, जिससे प्रदेश के 891 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 450 से अधिक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं, वीरांगनाओं को 1 हजार बीघा से अधिक कृषि भूमि और फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविदा पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 2 वर्षों तक 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नए जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गए हैं तथा सैनिक परिवारों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वेबसाइट शुरू की गई है। साथ ही, जिला स्तर पर 400 से अधिक शिविर आयोजित कर पेंशन संबंधी प्रकरणों का समाधान किया गया है।

बिना पेपर लीक आयोजित करवाई 410 से अधिक परीक्षाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसान, गरीब, महिला और युवा सहित प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित करवाई गई हैं। जिनसे 1 लाख 93 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं, 3 लाख 70 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्राओं को 13 लाख 85 हजार साइकिलें और 46 हजार स्कूटियां वितरित की गई हैं। सरकार ने छात्राओं को स्कूटी एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड दिया जा रहा है।

संवाद के दौरान प्रदेशभर से आए कायमखानी समाज के लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

दिल्ली में राहुल गांधी का जलसा सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसाः अमित शाह

आवाज़ ए तसनीम





चंडीगढ़। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की रैली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता शामिल हुए।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर रैली करने के लिए इंडिया ब्लॉक की आलोचना की और कहा, जिस दिन सिखों का नरसंहार हुआ था, उसी दिन उन्हें रैली आयोजित करनी थी।

सिख विरोधी दंगों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी का जलसा सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे काले दिवस पर रैली आयोजित करने के लिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से नफरत के अलावा कुछ नहीं निकला।

शाह ने कहा, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी प्रतीकात्मक संसद में ही बैठे रहिए। आपका नंबर कभी नहीं आएगा।

शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, झूठ बोलना, अराजकता फैलाना और संसद को काम नहीं करने देना, यही आपकी फितरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक नवंबर, 1984 को सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में हजारों सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया। कई सिखों को अपने घर छोड़ने पड़े, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई बहनें विधवा हो गईं और अनेक लोगों के घर जला दिए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था।

मैंने यह बयान टीवी पर देखा था और उसे जीवनभर नहीं भूल सकता। उन्होंने (राजीव गांधी) कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।उन्होंने कहा कि हजारों सिखों की हत्या के बाद ऐसी टिप्पणी सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल लोगों के सभी मामलों को फिर से खोला गया। उन्होंने कहा कि दंगों में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को जेल भेजा गया।

अमित शाह ने कहा, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तो हमने दंगाइयों के खिलाफ सभी केस फिर से खोले, हर पीड़ित को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, और यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाएं। भारत ने पहले कभी नहीं देखा था–और न ही आगे कभी देखेगा–इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा भड़काए गए दंगे। शाह ने कहा, हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुरोध किया कि वे 1, 2 और 3 नवंबर को इवेंट न करें–जिस दिन सिख विरोधी दंगे हुए थे–क्योंकि इससे सिख समुदाय, जिसमें माताएं, बहनें और बच्चे शामिल हैं, की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। लेकिन वे अड़े रहे। विदेश से उसी दिन रैली करने का ऑर्डर दिया गया जिस दिन हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया था। गुरुओं की इस धरती से, मैं इस घटिया कोशिश की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं। भारत और पंजाब इसे कभी नहीं भूल पाएंगे।

महादेव सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया

आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर, महादेव ऐप अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ओमान भेजी गई सीबीआई की एक विशेष टीम उसे अपने साथ भारत वापस ले आई है। अब सोमवार को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।

सौरभ चंद्राकर सीबीआई के दो मामलों में वांछित है, जिनमें पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वह ईडी के एक मामले में भी आरोपी है। यह प्रत्यर्पण उन भगोड़ों को वापस लाने के भारत के लगातार प्रयासों में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो विदेशों से भारतीय नागरिकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चलाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच में सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट्स में से एक था, जिसे भारत के बाहर से चलाया जा रहा था।

मुस्लिम समाज की तरक्की का रोडमैप: शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती

आवाज़ ए तसनीम



पवित्र कुरआन में कहा गया है: 'निस्संदेह, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वे खुद अपने भीतर बदलाव न लाएं। '

यह कालातीत सिद्धांत भारतीय मुसलमानों के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करता है, क्योंकि वे राष्ट्र के भविष्य में सार्थक योगदान देना चाहते हैंदृप्रगति का रोडमैप बनाने के लिए, भारतीय मुसलमानों को सबसे पहले भारत के अद्वितीय चरित्र को समझना होगा। कई अन्य देशों के विपरीत जो अपेक्षाकृत एकरूप हैं, भारत एक विशाल, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक सभ्यता है। यह राज्यों का एक संघ है, जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक रीति-रिवाज हैं।

यह पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उर्दू सभी भारतीय मुसलमानों की भाषा नहीं है। लगभग 45 प्रतिशत भारतीय मुस्लिम तमिल, तेलुगु, असमी, बंगाली, मलयालम और अन्य भाषाएं बोलते हैं। इसलिए, एक समान, उत्तर भारत-केंद्रित या उर्दू-केंद्रित दृष्टिकोण पूरे देश में मुसलमानों की विविध वास्तविकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है।

भारत के भविष्य में मुस्लिम योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई किसी भी रणनीति की जड़ें विविधता के सिद्धांत में होनी चाहिए।भारतीय संविधान सभी नागरिकों (मुसलमानों सहित) के लिए एक मार्गदर्शक और अधिकारों का गारंटर दोनों है। अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करने के साथ-साथ, मुसलमानों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भी समझना और पूरा करना होगा।

ऐतिहासिक रूप से, मुसलमान या तो मुस्लिम-बहुसंख्यक समाजों में रहे हैं या उन देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहे हैं जहाँ उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे।

भारतीय मुसलमान और लोकतंत्र: संवैधानिक मूल्यों से जुड़ाव क्यों जरूरी?

आवाज़ ए तसनीम



मुस्लिम जीवन शैली को संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ना या सामंजस्य बिठाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? राजनीतिक रूप से, मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर खुद को धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) दलों के साथ जोड़ा है, सिवाय हैदराबाद, केरल और असम जैसे कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर, जहाँ पहचान की राजनीति (आइडेंटिटी पॉलिटिक्स) अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुसलमानों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक लंबा जुड़ाव रहा है, साथ ही उन्होंने बदलते राजनीतिक हालातों और चुनावी ज़रूरतों के जवाब में क्षेत्रीय दलों की ओर भी अपना समर्थन स्थानांतरित किया है।

हिलाल अहमद की पुस्तकसियासी मुसलमानहमें मुस्लिम राजनीति के इर्द-गिर्द बने कई मिथकों को समझने और उन्हें चुनौती देने में मदद करती है। हाल के वर्षों में, विधायी निकायों (संसदों व विधानसभाओं) में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में लगातार गिरावट आई है, जिसका एक कारण जातियों की राजनीति का पुनर्गठन और भाजपा की चुनावी सफलता भी है।

यह राजनीतिक यथार्थ समुदाय के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। इसे समुदाय के नेताओं को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि मुसलमान किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में भाग लेते हैं।

मैं आगे बढ़ने के एक संभावित रास्ते के रूप में 'इंस्ट्रूमेंटल स्टेकहोल्डिंग' (उपकरण-आधारित हिस्सेदारी) के विचार का सुझाव देती हूँ। राजनीति को अक्सर चुनावों और धर्मनिरपेक्षता के इर्द-गिर्द होने वाली बयानबाजी तक ही सीमित कर दिया जाता है।

इंस्ट्रूमेंटल स्टेकहोल्डिंग को महज़ धार्मिक आधार पर वोट देने के बजाय औपचारिक, अधिकार-आधारित जुड़ाव के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी के रूप में समझा जा सकता है, जो समुदायों को राज्य को जवाबदेह ठहराने और कल्याणकारी लाभ सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को संवैधानिक गारंटियों की प्राप्ति के लिए एक शांतिपूर्ण और निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है। कुछ हालिया घटनाएँ बताती हैं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्से ऐसे लोकतांत्रिक रुख की ओर बढ़ रहे हैं।

यूसीसी पर बहस और मुस्लिम विरोध

बंगाल में, मुसलमानों के एक वर्ग ने गोहत्या का विरोध किया है; मुसलमानों ने किसान आंदोलनों जैसे जन आंदोलनों में भाग लिया; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्यायों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियास्वरूप बड़ी संख्या में लोगों ने सीएए (१) के खिलाफ शांतिपूर्ण, संवैधानिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।

मंदिर-मस्जिद के पास मीट की दुकान बंद कराई:खैर में मुस्लिम समाज ने पुलिस से की थी दुकान बंद कराने की मांग



खैर में मुस्लिम समाज ने पुलिस से की थी दुकान बंद कराने की मांग

आवाज़ ए तसनीम

खैर के पैंठ मैदान के पास मंदिर और मस्जिद के नजदीक चल रही मीट की दुकान बंद करा दी गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस संबंध में खैर पुलिस को शिकायत दी थी।

लोगों ने बताया कि पैंठ मैदान के पास बाबा बाली मस्जिद है, जहां मुस्लिम समाज के लोग नियमित नमाज अदा करते हैं। मैदान के सामने सत्यनारायण मंदिर में रोज महिला और पुरुष पूजा करने आते हैं। उनका आरोप है कि दुकान के कारण धार्मिक लोगों को असुविधा होती है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस जमीन पर दुकान चल रही थी, उसे लेकर अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। उन्होंने आशंका जताई कि विवादित जमीन पर दुकान चलने से कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द की समस्या हो सकती है। लोगों ने खैर पुलिस और पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी।

सीओ खैर अभिषेक पटेल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मीट की दुकान बंद करा दी गई है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस्लामिक चिंतन में भारत की भूमिका, इतिहास से भविष्य तक

आवाज़ ए तसनीम



भारतीय इस्लामिक विद्वानों, यानी उलेमा-ए-हिंद ने एक ऐसे धर्मशास्त्र की रचना की है जिसकी जड़ें जितनी कुरान में हैं, उतनी ही भारत की अनूठी सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं में भी हैं। इन्होंने ही वैश्विक मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन किया है।

18वीं शताब्दी कई बड़े बदलावों की गवाह बनी, जैसे,मुगल साम्राज्य का पतन, यूरोपीय उपनिवेशवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति। भारतीय इस्लामिक विद्वानों ने एक जीवंत, अक्सर मतभेदों से भरी, लेकिन बेहद गहन आंतरिक बहस का नेतृत्व किया, जिसने आगे चलकर वैश्विक मुस्लिम उम्माह (समुदाय) को प्रभावित किया। ये आंदोलन केवल नीरस अकादमिक बदलाव नहीं थे, बल्कि एक जीवंत 'तहज़ीब' (सभ्यता) थे, जो वक्त की मांग का जवाब दे रहे थे।

शाह वलीउल्लाह देहलवी को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण एशियाई इस्लामिक सोच की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जा सकता है, जो अगले तीन दशकों तक दुनिया पर हावी रही। वे 'दीवार पर लिखी इबारत' को पढ़ सकते थे और उन्होंने समझ लिया था कि इस्लाम को अभिजात वर्ग के दरबारों से निकलकर आम आदमी के दिल तक पहुँचना होगा।

वलीउल्लाह ने पवित्र कुरान का फ़ारसी में अनुवाद करके इस्लामिक समझ में 'लोकतंत्र' का समावेश किया। यद्यपि उन्हें रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के कोप का भाजन बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन व्यापक भारतीय जनमानस के लिए ईश्वरीय ज्ञान के द्वार खोल दिए जो अरबी भाषा नहीं समझते थे।

वे ततबीक (संश्लेषण/समन्वयन) में विश्वास रखते थे, यानी कानूनविदों की वैधानिकता को सूफियों की आध्यात्मिक गहराई के साथ जोड़ना। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, 'मुस्लिम दुनिया की नब्ज शाह वलीउल्लाह के विचारों से ही धड़कने लगी थी। '

मुस्लिम समाज की तरक्की का रोडमैप: शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती

वलीउल्लाह के लिए इस्लामिक शिक्षाएँ मूल रूप से 'उत्तरजीविता का धर्मशास्त्र' (थियोलॉजी ऑफ सर्वाइवल) थीं। कार्ल मार्क्स से लगभग एक सदी पहले, उन्होंने न्याय (अद्ल) पर आधारित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की वकालत की और यह जोर देकर कहा कि गरीबी और असमानता से ग्रसित समाज कभी भी वास्तव में एक इस्लामिक समाज नहीं हो सकता।

उन्होंने इस्लामिक कानून का एक तर्कसंगत बचाव पेश किया और इसे केवल अंधविश्वास या डोग्मा के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक कल्याण के लिए बनाई गई एक प्रणाली के रूप में रेखांकित किया। बाद में, उनके बेटों और पोतों ने इस आंदोलन को जीवित रखा और कुरान का उर्दू में अनुवाद किया, जिससे इस्लामिक ज्ञान को क्षेत्रीय भाषा (आम जनभाषा) की वास्तविकता बना दिया गया।

शाह वलीउल्लाह ने सिद्धांत दिया और देवबंद मदरसे ने उस सिद्धांत को समाज पर लागू किया। 1857के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले इस्लामिक विद्वानों द्वारा स्थापित, दारुल उलूम देवबंद केवल एक धार्मिक स्कूल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरोध का एक बड़ा संस्थान था।

मौलाना मुहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही,इन दोनों ने 1857में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। वे समझ गए थे कि भारत पर अंग्रेजों की पकड़ एक क्रूर सच्चाई बन चुकी थी। संकट के इस समय में, उलेमा को भारत पर हो रहे सांस्कृतिक आक्रमण का विरोध करके औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन की अगुवाई करनी थी।

मुस्लिम संगठनों के सामने चुनौती: परंपरा, सुधार और आधुनिकता



आवाज़ ए तसनीम

मुस्लिम समुदाय के भीतर अनुदार (कंजर्वेटिव) आवाज़ों को बढ़ावा देने वाले तंत्र (इकोसिस्टम) को चुनौती दिए जाने की ज़रूरत है।एक स्वस्थ समुदाय को केवल ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती जो परंपराओं को सुरक्षित रखें, बल्कि ऐसे मंचों की भी ज़रूरत होती है जो समकालीन वास्तविकताओं के साथ बहस, सुधार और रचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करें।लोगों को सामूहिक सामुदायिक पहचान के इर्द-गिर्द संगठित करने की ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की विरासत स्वतंत्र भारत में भी आगे बढ़ाई गई।

गणराज्य के संवैधानिक ढांचे के भीतर, राजनीतिक जुड़ाव, कानूनी कार्रवाई और सामाजिक आंदोलनों के ज़रिए द्यश्रद्धड्ढड्ड4द्धठ्ठद् करना (पैरवी करना) तथा समुदाय के हितों को सुरक्षित करना और राज्य से मिलने वाले लाभों को अधिकतम करना, वैध तरीकों के रूप में स्थापित हुआ।

औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित कई संगठन धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) भारत में फलते-फूलते रहे, वहीं नए संगठनों का भी उदय हुआ। आज़ादी के बाद मुसलमानों की प्रत्यक्ष राजनीतिकामबंदी (मोबिलाइजेशन) अपेक्षाकृत सीमित हो जाने के कारण, कई सामुदायिक संगठनों ने अपना मुख्य ध्यान धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकारी गतिविधियों पर केंद्रित किया। विशेष रूप से धार्मिक संगठनों ने, विश्वास कायम करने और अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए सामाजिक पहलों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई संगठन आज भी शिक्षा, दान और सामुदायिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 1972में स्थापित ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कथित खतरों से मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के वास्ते विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एक साथ लाने का प्रयास किया।

इसके साथ ही, मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष और सुधारवादी मंचों पर भी संगठनों की स्थापना की। 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडल' और 'इंडियन सेक्युलर स्पष्द्धद्गह्व4' की शुरुआत हामिद दलवाई ने की थी, जबकि 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म' की स्थापना असगर अली इंजीनियर ने की थी। यह कोई पूरी सूची नहीं है।

यह संक्षिप्त इतिहास एक बात स्पष्ट करता हैः भारत में मुसलमानों ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विचारों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम (दायरे) का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का निर्माण और संचालन किया है।

भारत में मुस्लिम संगठनों का इतिहास औपनिवेशिक बंगाल तक जाता है। बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम हितों की रक्षा और उन्नति करते हुए ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता की 'अंजुमन-ए-इस्लामी' की स्थापना 1855में एक शुरुआती संगठन के रूप में की गई थी।

सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए 1863 में 'मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी' की स्थापना की। कोलकाता में सैयद अमीर अली द्वारा 1877 में स्थापित 'सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन' ने मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए काम किया।

देवबंद मदरसा आंदोलन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्थागत रूप लिया और बाद में पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। समय के साथ अन्य प्रमुख संगठन भी उभरे, जिनमें 1906में 'ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग', 1894 में 'नदवतुल उलेमा' और 1929 में 'अल-अहरर आंदोलन' शामिल हैं।

दक्षिण भारत में, 1921 में स्थापित 'केरल नदवतुल मुजाहिदीन' और 1926में स्थापित 'समस्त केरल जमीयतुल उलेमा' जैसे संगठन प्रभावशाली बने। 1919 में स्थापित 'जमियत उलेमा-ए-हिंद' ने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष में भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्या मुस्लिम संगठन संवैधानिक नैतिकता के विरोधी हैं?

समकालीन भारत में मुस्लिम संगठनों का विश्लेषण करते समय यह पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। मुसलमानों का विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक आधारों पर संगठित होना न तो स्वाभाविक रूप से हानिकारक है और न ही कोई ऐसी बात जिससे मुंह फेरा जाए।

लोकतंत्र में नागरिकों को अपने विश्वासों, हितों और आकांक्षाओं के अनुसार खुद को संगठित करने का अधिकार है। फिर भी, मुस्लिम संगठनों के इर्द-गिर्द लगातार आशंकाएं बनी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण (कंसोलिडेशन) का मिथक है।

कई अध्ययनों ने इस चुनावी धारणा को चुनौती दी है और यह तर्क दिया है कि अन्य नागरिकों की तरह मुसलमान भी आजीविका, विकास, शासन, पहचान और धर्मनिरपेक्ष विचारों सहित कई कारकों के आधार पर अपने राजनीतिक विकल्प चुनते हैं।

एक अन्य आम आरोप यह लगाया जाता है कि मुस्लिम संगठन एकाधिकारी (मोनोलिथिक) हैं और पर्सनल लॉ तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के कारण अलगाववाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

यह भी एक अतिसरलीकरण है। शाह बानों मामले और अनगिनत अन्य मुद्दों के इर्द-गिर्द चल रही बहसों में भारतीय मुसलमानों के बीच विचारों की विविधता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर भी, अनुदार आवाज़ों को अक्सर असमान रूप से अधिक ध्यान मिलता है, जबकि समुदाय के भीतर मध्यममार्गी, सुधारवादी और धर्मनिरपेक्ष आवाज़ें अपेक्षाकृत अदृश्य ही बनी रहती हैं।

भारतीय सशस्त्र बल: देश के युवाओं के लिए एक पावन पुकार



आवाज़ ए तसनीम

मैं एक ऐसे प्रतिबद्ध सैन्य परिवार से आता हूँ जहाँ देश सेवा और सैनिक बनने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मेरे पिता लेफ्टिनेंट जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए, जो देश के दूसरे सबसे उच्च सैन्य पद 'डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ' (उप थल सेनाध्यक्ष) के रूप में सेवारत रहे।

दुनिया में कुछ पेशे हमें धन-दौलत देते हैं, तो कुछ समाज में रुतबा और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे विरले रास्ते होते हैं जो जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देना एक ऐसा ही मार्ग है।

यह महज कोई नौकरी या करियर नहीं है। यह राष्ट्र के प्रति एक अटूट समर्पण है, करोड़ों जिंदगियों की रक्षा करने का एक वचन है और एक ऐसा सफर है जो साधारण युवाओं को साहस, त्याग और सम्मान के प्रतीक में बदल देता है। मैंने खुद भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पूरे सम्मान के साथ अपनी सैन्य सेवा पूरी की है। मेरे चाचा भी थल सेना में थे। मेरे जीजाजी, कमोडोर रिज़वान अली शाह, कुछ महीने पहले ही नौसेना (इंडियन नेवी) से एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरी मौसेरी बहन के पति भारतीय वायु सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी अनुभव के आधार पर मैं अपने देश के मुस्लिम युवाओं को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ।

आज के भारतीय युवाओं के लिए,विशेषकर एक ऐसी दुनिया में जो अनिश्चितताओं, दबावों और उलझनों से भरी है,सैनिक बल एक बेहद अनमोल चीज प्रदान करते हैंः'जीवन का असली मकसद'।

भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना केवल सैनिक तैयार नहीं करतीं, बल्कि वे चरित्र का निर्माण करती हैं। वे अनुशासन, विपरीत परिस्थितियों से उबरने का जज्बा (रेजिलिएंस), आत्म-सम्मान और नेतृत्व क्षमता सिखाती हैं। वे युवाओं को डर से उबरना और कठिन से कठिन पलों में भी सीना तानकर खड़ा होना सिखाती हैं।

विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं के लिए, भारतीय सशस्त्र बल एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देते हैं। वे इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता। देश की वर्दी में न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख और न ही कोई ईसाई। वहाँ केवल एक ही पहचान होती हैःभारतीय।

यूसीसी पर बहस और मुस्लिम विरोध

आवाज़ ए तसनीम



भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता - यूसीसी) के साथ संबंध जितना कानूनी रहा है, उतना ही राजनीतिक भी रहा है।हाल के वर्षों में, यूसीसी के लागू होने से तीव्र बहस और असहमति पैदा हुई है। समर्थकों का तर्क है कि अलग-अलग पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कानूनों) के होने से अनिश्चितता और संघर्ष पैदा होता है, जिससे कानूनी विवादों का समाधान करना अधिक कठिन हो जाता है। दूसरी ओर, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक नेताओं ने इस विचार में कई कमियों की ओर इशारा किया है और इसके संभावित परिणामों को लेकर वैध चिंताएं व्यक्त की हैं।वर्ष 2025 में, उत्तराखंड संवैधानिक आकांक्षा को लागू करने योग्य कानून में बदलने वाला पहला राज्य बन गया। असम और गुजरात भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं।

फिर भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में 'भारत' का आह्वान किया गया है जो एक राष्ट्रीय आकांक्षा का संकेत देता है, लेकिन व्यवहार में पार्टी ने राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है।

आलोचकों का कहना है कि परिवार और उत्तराधिकार के कानून समवर्ती सूची (कॉन्करेंट लिस्ट) के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अनुच्छेद 44 की परिकल्पना के अनुसार, किसी कोड को 'भारत के पूरे क्षेत्र में' प्रभावी बनाने के लिए, उनका तर्क है कि इसे संसद से ही शुरू होना चाहिए।

उनका मानना है कि राज्य-दर-राज्य का यह बिखरा हुआ तरीका उस संवैधानिक दृष्टिकोण को पूरा नहीं करता; इसके बजाय, इससे देश भर में कानूनी विसंगति की नई परतें पैदा होने का जोखिम है।

सरकार पर आलोचकों द्वारा यह आरोप भी लगाया गया है कि वह उन मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नए कानूनों का उपयोग कर रही है जो शरिया-आधारित पर्सनल लॉ के तहत प्रथाओं का पालन करते हैं, विशेष रूप से बहुविवाह और तलाक के कुछ ऐसे रूप जो अब यूसीसी के तहत प्रतिबंधित हैं।

उसी समय, भाजपा के 2024 के घोषणापत्र में महिलाओं के अधिकारों पर काफी जोर दिया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि एक ऐसे यूसीसी के बिना लैंगिक समानता हासिल नहीं की जा सकती जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता हो।

जैसे-जैसे यह विधायी गति तेज हो रही है, पुरानी बातें नए सिरे से और तात्कालिकता के साथ सामने आ गई हैंः भारत जैसे संवैधानिक रूप से जटिल देश के लिए यूसीसी का वास्तव में क्या अर्थ है?

अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, इसका अल्पसंख्यकों (मुसलमानों सहित) के लिए, और उससे भी अधिक दबाव के साथ, उन मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या अर्थ है, जो खुद को एक ऐसी बहस के केंद्र में पाती हैं जिसे वे गलत समझने का जोखिम नहीं उठा सकतीं?

उनकी वैध शिकायतों को बहुत बार पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है , यह सब राज्य की राजनीतिक गणना और उनके अपने समुदाय के नेतृत्व के पितृसत्तात्मक पहरेदारी के चलते हुआ है।

अपने सबसे बुनियादी स्तर पर, यूसीसी बहस महिलाओं को समान नागरिकों के रूप में मान्यता देने के बारे में भी है, जो विवाह के मामलों में वैधानिक सुरक्षा की हकदार हैं, जिसमें बहुविवाह के खिलाफ सुरक्षा, न्यायसंगत तलाक के अधिकार और समान उत्तराधिकार शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ, अपने वर्तमान स्वरूप में, लैंगिक समानता के संवैधानिक आदर्शों पर खरा उतरने में लगातार असफल रहता है।

यूसीसी और धार्मिक विरोध की राजनीति

यूसीसी का विवादास्पद इतिहास वर्तमान राजनीतिक दौर से सात दशक पुराना है। जब जवाहरलाल नेहरू ने कानूनी एकरूपता की नींव रखने का प्रयास किया, तो उन्हें यह क्षेत्र एक बार में पार करने के लिए बहुत संवेदनशील लगा।जैसा कि इतिहासकार रोमिला थापर ने उल्लेख किया है, नेहरू अपने सामने आए भारी विरोध को देखते हुए पूरी दूर तक नहीं जा सके।

इसके बजाय उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ के सम्हलीकरण और सुधार को चुना , जो कि एक अधिक राजनीतिक रूप से प्रबंधनीय पहला कदम था। हालांकि वह कदम भी काफी भड़काने वाला साबित हुआ था। मद्रास में ऑल इंडिया हिंदू महासभा द्वारा हिंदू कोड बिल को एक 'आत्मघाती मूर्खता' के रूप में वर्णित किया गया था जो कुल मिलाकर हिंदू समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालती थी।

सात दशक बीत जाने के बाद, वे चिंताएं गायब नहीं हुई हैं; बल्कि, उन्होंने रूप बदल लिया है। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले रूढ़िवादी हिंदू रूढ़िवादियों द्वारा जो भूमिका कभी निभाई गई थी, वही भूमिका अब यूसीसी बहस में मुस्लिम पर्सनल लॉ में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने वाले मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व के कुछ हिस्सों द्वारा निभाई जा रही है।

मुस्लिम समुदाय के भीतर काफी विरोध सामने आया है, जिसमें आलोचकों ने आरोप लगाया है कि भाजपा एक ऐसे 'हिंदू कोड' को पेश करने का प्रयास कर रही है जिसे वे यूसीसी की आड़ में अनिवार्य बताते हैं।

اندرا گاندھی کا قتل اور وہ فون کال جس کے بعد انڈیا۔ پاکستان کا کرکٹ میچ روکنا پڑا

31 اکتوبر 1984 کو پاکستان کے مشرقی شہر سیالکوٹ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوسرے ایک روزہ میچ کے دوران انڈیا کے بلے باز دلیپ وینگسرکر اپنی پہلی ایک روزہ بین الاقوامی سنچری کے قریب تھے جب انھوں نے پاکستانی کھلاڑی جاوید میانداد کو تھرڈ مین کی پوزیشن سے اپنی جانب آتے دیکھا۔ دلیپ وینگسرکر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس وقت ان کے ذہن میں کئی خیالات آئے۔ 'میں نے سوچا کہ شاید پاکستانی کپتان ظہیر عباس مجھے دباؤ میں لانے کیلئے فیلڈر کو قریب کھڑا کرنے کی حکمتِ عملی اپنا رہے ہیں۔ یا پھر شاید جاوید میانداد اپنی پرانی عادت کے مطابق اوورز کے درمیان چھیڑ چھاڑ یا میری توجہ بٹانے کیلئے کوئی اشتعال انگیز بات کرنے آ رہے ہیں۔' لیکن میانداد کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وینگسرکر حیران رہ گئے۔ 2009 میں دیے گئے اس انٹرویو میں وینگسر کرنے بتایا کہ 'وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ انھوں نے تماشائیوں میں سے کسی شخص سے سنا ہے کہ انڈیا کی وزیراعظم اندرا گاندھی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں لوگ میچ دیکھنے کیلئے اپنے ساتھ ٹرانزسٹر ریڈیو لایا کرتے تھے اور اسی طرح انھیں اس خبر کا پتا چلا تھا۔

'سنیل گواسکر کی قیادت میں انڈین ٹیم کا پاکستان کا دورہ

سنیل گواسکر کی قیادت میں انڈین ٹیم تین ٹسٹ اور تین ایک روزہ میچ کھیلنے کیلئے پاکستان کے دورے پر تھی۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان لاہور اور فیصل آباد میں کھیلے گئے ابتدائی دونوں ٹسٹ میچ زیادہ رنز بننے کے باوجود ڈرا ہوئے تھے جبکہ پاکستان کوئٹہ میں کھیلا گیا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ 46 رنز سے جیت چکا تھا۔ اب دونوں ٹیموں کو 31 اکتوبر 1984 کو سیالکوٹ میں دوسرا ایک روزہ میچ کھیلنا تھا۔ اس دورے سے قبل سیالکوٹ میں ایسا کوئی ہوٹل موجود نہیں تھا جہاں مہمان ٹیموں کو ٹھہرایا جا سکے۔ اُس وقت سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر اسماعیل قریشی نے جریدے 'دی کرکٹ منتھلی' کے لکھاری دانیال رسول کو بتایا تھا: 'ہم عام طور پر مہمان ٹیموں کو لاہور میں ٹھہراتے تھے۔ میچ والے دن صبح چار بجے انھیں جگا کر سیالکوٹ لاتے اور میچ کے بعد واپس لاہور لے جاتے تھے۔' انڈین ٹیم پہلی مہمان ٹیم تھی جسے سیالکوٹ کے ایک نئے تعمیر شدہ ہوٹل میں ٹھہرنا تھا۔ سیالکوٹ کے صحافی عبدالشکور مرزا کے مطابق دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اس بات پر خوش تھے کہ انھیں میچ والے دن علی الصبح چار بجے اٹھ کر دو گھنٹے سے زیادہ کا سفر نہیں کرنا پڑا۔ دانیال رسول کے مطابق انڈین ٹیم کے ساتھ کئی صحافی بھی آئے تھے لیکن نیا ہوٹل سب کے قیام کیلئے کافی نہیں تھا۔ چنانچہ، اسماعیل قریشی کے مطابق، 'انتظامیہ نے علاقے کے چند نسبتاً آرام دہ گھروں کے مالکان سے درخواست کی کہ وہ رات کیلئے کچھ انڈین مہمانوں کے قیام کا انتظام کریں اور انہوں نے خوش دلی سے یہ درخواست قبول کر لی۔' عبدالشکور مرزا نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ یہ میچ اس لحاظ سے بھی یادگار تھا کہ انڈین کھلاڑیوں کو لاہور کے بجائے سیالکوٹ میں ٹھہرانے کیلئے وزیر آباد چوک کے قریب میرٹن نامی ایک نیا ہوٹل تعمیر کیا گیا تھا جبکہ پاکستانی ٹیم کو شہر کے صنعت کاروں کے گھروں میں ٹھہرایا گیا۔ روزنامہ جنگ کیلئے اس میچ کی کوریج کرنے والے عبدالشکور مرزا کے مطابق انہیں میچ سے ایک روز قبل دونوں ٹیموں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کا موقع بھی ملا۔ ان کے مطابق انڈین کھلاڑی پہلی مرتبہ سیالکوٹ میں ایک روزہ میچ کھیلنے پر خاصے خوش تھے، خصوصاً اس شہر میں جو دنیا بھر میں کھیلوں کا سامان بنانے کیلئے مشہور ہے۔ مرزا کے بقول سنیل گواسکر نے انھیں بتایا تھا: 'خوشی ہے کہ جو شہر دنیا بھر میں کھیلوں کا سامان بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اسی شہر سے تعلق رکھنے والے ظہیر عباس کی کپتانی میں میچ ہے۔ کل دیکھیں گے وہ اپنے شہر کو کیسا کھیل دکھاتے ہیں۔' دوسری طرف ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ اپنے آبائی شہر میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے جو دلی خوشی ہو رہی ہے، اسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ 'میچ سیالکوٹ کے جناح سٹیڈیم میں ہونا تھا، جو مرزا کے مطابق پاکستان کے قدیم ترین کرکٹ میدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے مطابق برطانوی دور میں 1920 کی دہائی میں تعمیر ہونے والے اس میدان کو ابتدا میں کوئلی پارک کہا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا نام جناح پارک رکھا گیا جبکہ 1979 میں اس کی تزئین و آرائش کے بعد اسے جناح اسٹیڈیم کا نام دیا گیا۔ یہی میدان 1976 میں پاکستان میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی میزبانی بھی کر چکا تھا۔ مرزا کے مطابق اس میچ کے لیے تیار کی گئی پچ کی مٹی نندی پور سے لائی گئی تھی۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سیالکوٹ میں فلڈ لائٹس بھی موجود نہیں تھیں۔ اسی لیے سیریز کے ایک روزہ میچوں کے لیے دونوں ٹیموں کو 40،40 اوور دیے گئے تھے تاکہ کھیل وقت پر مکمل ہو سکے۔

پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا

سنیل گواسکر کے زخمی اور کپل دیو کے فٹ نہ ہونے کی وجہ سے انڈیا اس میچ میں آل راؤنڈر مہندر امرناتھ کی قیادت میں میدان میں اترا تھا۔ اس میچ کے بعد مہندر امرناتھ کو دوبارہ کبھی انڈین ٹیم کی قیادت کیلئے زیرِ غور نہیں لایا گیا۔ میچ معمول کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا اور تماشائی کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مرزا کے مطابق مقامی نوجوان مصور طارق نسیم نے پویلین میں سنیل گواسکر اور دیگر کھلاڑیوں کو اپنے ہاتھ سے بنائے گئے پورٹریٹ بھی پیش کیے۔ میدان میں انڈیا کی جانب سے انشومن گائیکواڈ اور غلام پارکر نے اننگز کا آغاز کیا۔ 53 رنز تک دونوں اوپنرز مدثر نذر کا شکار بن چکے تھے۔ تاہم دلیپ وینگسرکر اور سندیپ پاٹل نے اسکور 196 تک پہنچا دیا۔ یہ شراکت اُس وقت ختم ہوئی جب سندیپ پاٹل 59 رنز بنا کر توصیف احمد کی گیند پر بولڈ ہوئے۔ لیکن میدان کے باہر صورتحال بدلنا شروع ہو چکی تھی۔

وہ فون کال جس نے میچ روک دیا

'دی کرکٹ منتھلی' کو 2016 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈپٹی کمشنر اسماعیل قریشی نے بتایا کہ وہ میچ دیکھ رہے تھے جب تقریباً ساڑھے دس بجے پنجاب کے چیف سیکریٹری کا فون آیا۔ 1984 میں بھی ٹیلی فون کمپنی اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ ڈپٹی کمشنر جہاں کچھ وقت کے لیے تعینات ہو، وہاں لینڈ لائن ٹیلی فون ضرور نصب ہو۔ فون پر انھیں بتایا گیا کہ اندرا گاندھی کو دہلی میں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے میچ فوری طور پر منسوخ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسماعیل قریشی کے مطابق: 'میں حیران و پریشان سوچ رہا تھا کہ یہ حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا! میں اننگز کے درمیان سب کے سامنے جا کر کیسے کہتا کہ اپنا سامان اٹھائیں اور گھروں کو چلے جائیں؟ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال میچ جاری رہنے دیا جائے۔' مرزا کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسماعیل قریشی کو میچ



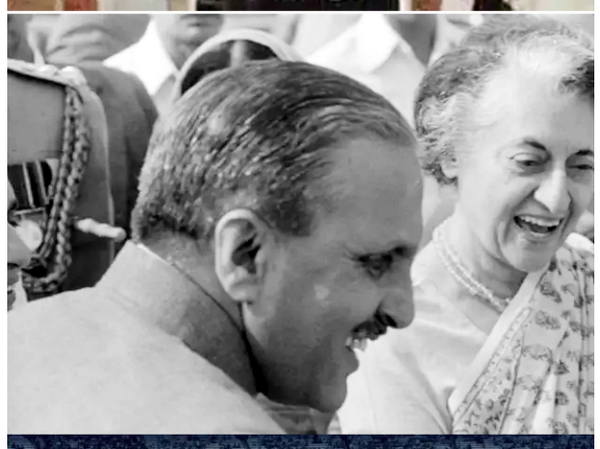



فوری ختم کرنے کی ہدایت ملی تھی، لیکن انھوں نے فیصلہ کیا کہ انڈین اننگز مکمل ہونے دی جائے۔ جب انڈیا کی اننگز ختم ہوئی تو ٹیم نے مقررہ 40 اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے تھے۔ دلیپ وینگسر کراپنی سنچری سے صرف چھ رنز دور تھے۔ انھوں نے 102 گیندوں پر ناقابلِ شکست 94 رنز بنائے جبکہ روی شاستری چھ رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ تھے۔ دانیال لکھتے ہیں کہ کھانے کا وقفہ اسماعیل قریشی کیلئے ٹیموں کو خبر دینے اور میچ ختم کرنے کا بہترین موقع تھا۔ وہ انڈین ڈریسنگ روم گئے اور سنیل گواسکر اور ٹیم منیجر راج سنگھ ڈونگر پور کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ اسماعیل قریشی یاد کرتے ہیں: 'سنیل گواسکر نے یہ خبر سن کر حیرت سے سانس کھینچی۔ میں نے انھیں صدر ضیاء الحق کے حکم کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔' 'انھوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ ٹیم سامان باندھے گی اور واپس جائے گی۔ میں نے انھیں بتایا کہ تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں اور گاڑیاں باہر لاہور روانگی کیلئے تیار کھڑی ہیں۔'

کچھ ہی دیر میں انڈین ٹیم لاہور روانہ ہو چکی تھی

انڈین اخبار 'دی ٹیلیگراف' کے صحافی لوکیندر پرتاپ ساہی لکھتے ہیں کہ دلیپ وینگسر کرنے بعد میں ان کے اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی کھلاڑی بھی اس خبر سے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ کپتان ظہیر عباس ہوں یا جاوید میانداد، وہ ہمارے ڈریسنگ روم میں آئے، تعزیت کی اور ہماری ہمت بندھائی۔ لوکیندر کے مطابق جناح اسٹیڈیم میں صحافیوں کیلئے کوئی میڈیا سنٹر نہیں تھا۔ 'اس لیے ایک چھوٹی سی عمارت کی چھت پر ہمارے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں ہمارے اردگرد تماشائی موجود تھے۔ 'بظاہر آل انڈیا ریڈیو کے کمنٹیٹرز کو اندرا گاندھی کے قتل کی خبر سب سے پہلے اپنے ہاٹ لائن ٹیلی فون پر ملی تھی۔ انہوں نے فوراً ٹیم منیجر راج سنگھ کو اس سے آگاہ کر دیا۔ راج سنگھ نے اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے حکام اور مقامی انتظامیہ سے رابطے شروع کر دیے، جس کی سربراہی سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر اسماعیل قریشی کر رہے تھے۔ 'راج سنگھ نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ ہم خاموشی سے ڈریسنگ روم کے قریب جمع ہو جائیں۔ راج سنگھ نے نم آنکھوں سے کہا: حضرات، ہماری وزیرِ اعظم کو گولی مار دی گئی ہے۔ ہم کھانے کے وقفے پر میچ ختم کر رہے ہیں۔' اس کے بعد انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ ایک ساتھ رہو، اِدھر اُدھر مت جاؤ۔۔۔ وقت حساس ہے۔' اس کے بعد ایک اہم مرحلہ باقی تھا: اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں شائقین کو میچ ختم ہونے کی اطلاع دینا۔ اسماعیل قریشی نے اعلان کیا کہ اندرا گاندھی کو گولی مار دی گئی ہے اور میچ ختم کر دیا گیا ہے۔ لوکیندر کے مطابق میچ ختم کرنے کا اعلان اس وقت کیا گیا جب گواسکر اور ان کے ساتھی سڑک کے راستے لاہور روانہ ہو چکے تھے۔ لوکیندر لکھتے ہیں کہ: 'ہم صحافی بھی تقریباً فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پہلے اس شاندار مہمان خانے میں پہنچے جہاں ہمارے قیام کا انتظام تھا، اور پھر مسلح محافظوں کی نگرانی میں لاہور روانہ ہوئے۔ 'لاہور میں ایک دن گزارنے کے بعد نئی دہلی سے پیغام آیا کہ ٹیم کو پہلی دستیاب پرواز سے وطن واپس پہنچنا ہے۔ چونکہ انڈین دار الحکومت میں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے، اس لیے انڈین ٹیم کراچی پہنچی اور وہاں سے دو الگ الگ گروپوں میں انڈیا روانہ ہوئی۔ 'ہم صحافیوں کو لاہور سے نئی دہلی جانے والی پی آئی اے کی پرواز میں ترجیحی نشستیں ملنے تک مزید ایک دن انتظار کرنا پڑا۔ ہوٹل میں، ہوائی اڈے پر اور دورانِ پرواز، بہت سے لوگوں نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا۔' عبدالشکور مرزا نے بتایا کہ یہ کرکٹ میچ سیالکوٹ کے شہریوں نے اپنے مثبت رویے سے مزید یادگار بنا دیا تھا۔ عبدالشکور مرزا کے مطابق جب جناح اسٹیڈیم میں انڈین وزیرِ اعظم اندرا گاندھی کے قتل کی خبر آئی تو یہاں موجود 25 ہزار سے زائد تماشائیوں نے اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا اور انتہائی منظم انداز میں اسٹیڈیم سے روانہ ہو گئے۔ مرزا کے مطابق بعد ازاں انڈیا کا دورہ ختم کر دیا گیا، پشاور میں کھیلا جانے والا اگلا ایک روزہ میچ اور کراچی کا آخری ٹسٹ بھی منسوخ کر دیا گیا۔

کھیل جاری رہنا چاہیے

دوسری جانب انگلینڈ کی ٹیم بھی 31 اکتوبر 1984 کو علی الصبح انڈیا کے دورے پر نئی دہلی پہنچی تھی، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد وزیرِ اعظم اندرا گاندھی کے قتل اور ملک میں سکھ مخالف تشدد کے باعث اس دورے کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے دورے پر موجود انڈین ٹیم کو تو واپس بلا ہی لیا تھا، اسے انگلینڈ کے خلاف ابتدائی میچ بھی منسوخ کرنا پڑے۔ ملک میں جاری فسادات کی وجہ سے انگلش ٹیم کوئی روز تک دہلی میں اپنے ہوٹل میں بند رہنا پڑا۔ بعد ازاں انڈین حکومت اور کرکٹ بورڈ کی اجازت سے وہ چار نومبر کو سری لنکا چلی گئی، جہاں نو روز پریکٹس اور چند میچ کھیلنے کے بعد حفاظتی یقین دہانیوں پر انڈیا واپس آ گئی۔ لیکن واپسی پر ایک اور واقعہ اس کا منتظر تھا۔ 27 نومبر کو پہلے ٹیسٹ کے آغاز سے ایک روز قبل، بمبئی میں برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر پرسی نورس کو صبح کام پر جاتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد انگلینڈ کا دورہ تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا، لیکن بالآخر ٹیم نے انڈیا میں قیام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم پانچ ٹسٹ میچوں کی سیریز کو مختصر کر کے چار ٹسٹ تک محدود کر دیا گیا۔ سابق انگلش کرکٹر اور صحافی وِک مارکس کے مطابق، بظاہر یہ ایک تباہ کن دورہ تھا۔ ممبئی میں پہلے ٹیسٹ سے ایک روز قبل برطانوی نائب ہائی کمشنر پرسی نورس کے قتل نے کھلاڑیوں کے خدشات مزید بڑھا دیے تھے۔ بیشتر کھلاڑی وطن واپس جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی سلامتی کا یقین نہیں تھا۔ اس کے باوجود دورہ جاری رہا، ڈیوڈ گاور کی قیادت میں انگلینڈ نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ انگلش ٹیم نے دہلی میں دوسرا اور مدراس میں چوتھا ٹسٹ جیتا، آخری ٹسٹ ڈرا کیا اور سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ مبصر ڈینیئل نورکراس کے مطابق، اکتوبر 1984 سے فروری 1985 تک انگلینڈ نے انڈیا اور سری لنکا کے 16 مقامات پر میچ کھیلے۔ یہ پہلی انگلش ٹیم تھی جس نے انڈیا میں ٹسٹ سیریز میں پیچھے ہونے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ اس دورے کے دوران دلیپ وینگسر کرنے اپنی واحد ایک روزہ بین الاقوامی سنچری بھی اسکور کی، یہ سنچری سیالکوٹ کے اس ادھورے میچ میں مکمل نہ ہو سکی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر 31 اکتوبر 1984 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیالکوٹ میں کھیلے گئے اس میچ کے اسکور کارڈ کے سامنے صرف دو الفاظ درج ہیں: 'نو رزلٹ' یعنی بے نتیجہ۔ مگر سیالکوٹ کے جناح اسٹیڈیم میں اس دن جو کچھ ہوا، اس کی کہانی محض ایک بے نتیجہ کرکٹ میچ کی نہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ایک بلے باز اپنی سنچری سے چند رنز دور تھا، ہزاروں شائقین میدان میں موجود تھے، اور پھر ایک خبر نے نہ صرف ایک میچ بلکہ ایک پوری سیریز کا رخ بدل دیا تھا۔

انرجی سیز فائر

امن کی شروعات یا مفادات کا کھیل؟

امریکی صدر، ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ماہ کے آغاز میں اعلان کیا کہ رُوس اور یوکرین ایک دوسرے کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے ''عارضی جنگ بندی'' کہا جا سکتا ہے، کیوں کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایک دوسرے کی توانائی کی تنصیبات ہی یوکرین اور رُوس کا بنیادی ہدف رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اعلان نے دُنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ یوکرین، روس جنگ شروع ہوئے اب پانچ سال سے زیادہ عرصہ بیت چُکا ہے۔ فروری 2021ء میں رُوسی صدر، ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کرنے کا حُکم دیا تھا اور وہ اِس وقت بھی یہ جنگ جاری رکھنے پر مُصر ہیں۔ یوکرین جنگ میں گزشتہ پانچ سال میں تقریباً ساڑھے چھے لاکھ افراد ہلاک ہو چُکے ہیں۔ اس میں بڑی تعداد رُوسی باشندوں کی ہے، جو تقریباً پانچ لاکھ سے زائد ہے، جب کہ یوکرین کے سوا لاکھ شہری لقمہ اجل بن چُکے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے، تو یہ شام جنگ کے بعد اس صدی کی سب سے خُوں ریز جنگ ہے۔ شام کی جنگ میں بھی رُوس نے دو سال تک شامی شہریوں پر بلا روک ٹوک بم باری کی تھی لیکن پھر بھی کام یاب نہ ہو سکا اور اس جنگ میں اپنے حلیف، بشارالاسد کی شکست کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں اپنا آخری فوجی اڈا خالی کر کے اپنے دوست کو سیاسی پناہ دے چُکا ہے۔ بہرکیف، امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد ''انرجی سیز فائر'' کا مقصد اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ٹرمپ کا اعلان اپنی جگہ لیکن ایک طرف اس کا فوری اثر یا ردِعمل سامنے نہیں آیا اور دوسری جانب رُوس کی جانب سے حملوں میں کمی بھی نہیں آئی، جس کے نتیجے میں شکوک و شُبہات اور کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ معاہدے کی نوعیت کیا ہے، کیوں کہ ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹیلی فون پر طویل بات چیت کے بعد یہ سیز فائر ہوا۔ گرچہ دو بڑی طاقتوں کے سربراہان کے ایسے اعلانات نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن ولادیمیر زیلنسکی کا، جو کہ یوکرین کے صدر اور متاثرہ فریق ہیں، موقف بھی خاصا اہم ہے، کیوں کہ جنگ بندی اُن کے مُلک میں ہونی ہے۔ پھر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پانچ سال کی جنگ کی تباہی حادثاتی تھی یا یہ سب پیوٹن کی سوچی سمجھی حکمتِ عملی کا حصّہ، کیوں کہ پانچ سال بعد سیز فائر کی بات اور وہ بھی صرف توانائی کے شُعبے کی حد تک، سمجھ سے بالاتر ہے۔

اِسے کسی بھی طور پر مکمل جنگ بندی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو صرف توانائی کی تنصیبات محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے اور کیا دونوں ممالک کے عوام اور شہروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس معاہدے سے ایک عام آدمی کی جان محفوظ ہو جائے گی؟ یہ جنگ بندی ہے یا کوئی کمرشل ڈِیل؟ کاروبار جاری رکھنے یا توانائی کی قیمت کم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اس معاہدے کی درخواست یوکرین نے کی تھی یا یورپی ممالک نے کہ جو اس تنازعے کے اہم ترین فریق ہیں اور یوکرین جنگ کو ''یورپ کی جنگ'' قرار دیتے ہیں۔ نیز، اس ضمن میں ان کا کیا موقف ہے؟ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ توانائی کی تنصیبات پر حملے روکنے پر فریقین نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن اس معاہدے کی، جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہوا، ایک بھی شِق سامنے نہیں آئی اور اگر کچھ عرصے بعد معاہدے کی تفصیلات سامنے لائی جاتی ہیں، تو کیا اُس وقت بات چیت کے بعد یہ سیز فائر ہوا۔ گرچہ دو بڑی طاقتوں کے سربراہان کے ایسے اعلانات نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن ولادیمیر زیلنسکی کا، جو کہ یوکرین کے صدر اور متاثرہ فریق ہیں، موقف بھی خاصا اہم ہے، کیوں کہ جنگ بندی اُن کے مُلک میں ہونی ہے۔ پھر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پانچ سال کی جنگ کی تباہی حادثاتی تھی یا یہ سب پیوٹن کی سوچی سمجھی حکمتِ عملی کا حصّہ، کیوں کہ پانچ سال بعد سیز فائر کی بات اور وہ بھی صرف توانائی کے شُعبے کی حد تک، سمجھ سے بالاتر ہے۔

اِسے کسی بھی طور پر مکمل جنگ بندی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو صرف توانائی کی تنصیبات محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے اور کیا دونوں ممالک کے عوام اور شہروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس معاہدے سے ایک عام آدمی کی جان محفوظ ہو جائے گی؟ یہ جنگ بندی ہے یا کوئی کمرشل ڈِیل؟ کاروبار جاری رکھنے یا توانائی کی قیمت کم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اس معاہدے کی درخواست یوکرین نے کی تھی یا یورپی ممالک نے کہ جو اس تنازعے کے اہم ترین فریق ہیں اور یوکرین جنگ کو ''یورپ کی جنگ'' قرار دیتے ہیں۔ نیز، اس ضمن میں ان کا کیا موقف ہے؟ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ توانائی کی تنصیبات پر حملے روکنے پر فریقین نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن اس معاہدے کی، جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہوا، ایک بھی شِق سامنے نہیں آئی اور اگر کچھ عرصے بعد معاہدے کی تفصیلات سامنے لائی جاتی ہیں، تو کیا اُس وقت تک ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہو سکے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فریقین حملے روکنے پر آمادہ ہو گئے ہیں جبکہ یوکرین کے صدر، زیلنسکی کا موقف یہ ہے کہ یوکرین رُوس کی توانائی کی تنصیبات پر حملے روکنے پر آمادہ ہے، بشرطیکہ دوسرا فریق یعنی رُوس بھی ایسا ہی کرے۔ تاہم، رُوس نے اس معاہدے کی تصدیق نہیں کی بلکہ رُوسی وزیرِ خارجہ، سرگئی لاروف نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یوکرین پر حملوں میں کسی قسم کا وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری طرف اعلان کے دوسرے ہی روز یعنی بارہ اکتوبر کو یوکرین نے رُوسی حملوں کی اطلاع دی۔

اگر فریقین میں انرجی سیز فائر ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین پر، جو رُوس سے چار گُنا چھوٹا مُلک ہے، خاصا فرق پڑے گا، کیوں کہ اس وقت اُسے بجلی سمیت دیگر صُورتوں میں توانائی کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر توانائی کی تنصیبات پر حملے روک دیئے جاتے ہیں، تو صرف بجلی گھروں ہی میں نہیں، عام شہریوں کے لیے بھی بجلی کی سپلائی مستحکم ہوگی۔ گھروں، اسپتالوں، کاروباری مراکز اور سرکاری دفاتر میں کام میں پڑنے والے خلل میں کمی آئے گی۔ نیز، رُوس سے اس کی ریفائنریز، ایندھن کے ذخائر اور برآمدی تنصیبات کو تحفّظ مل سکے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت رُوس کو دو اقسام کے دباؤ کا سامنا ہے، جن میں توانائی کی تنصیبات کا متاثر ہونا اور اقتصادی پابندیاں شامل ہیں۔ کریملن کو مشرقِ وسطیٰ کی جنگ کے دوران سستا تیل بیچنے کے وجہ سے وافر آمدنی حاصل ہوئی اور شاید اسی لیے اس کی خواہش ہے کہ اس کے حلیف، آبنائے ہُرمز اور باب المندب بند ہی رکھیں، کیوں کہ اس طرح اس کا تیل فروخت ہوتا رہے گا۔ آج کئی ممالک یہ کہتے ہیں کہ رُوس سے سستا تیل خریدا جائے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ایک جانب وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف رُوس سے تیل کی خریداری کی حمایت کرتے ہیں، حالاں کہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمائے ہی سے رُوس یوکرین جنگ کو طول دے رہا ہے اور اسی سبب گزشتہ پانچ برس سے زائد عرصے سے یہ جنگ جاری ہے اور پھر ویسے بھی رُوس طویل جنگوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کی پہلی جنگ نے مغربی اور جنوبی ایشیا کو غیر مستحکم کیا، جب کہ پاکستان کی معیشت تو اب تک تباہ حال ہے۔ دوسری جانب اس جنگ کے بعد مُلک میں شروع ہونے والی دہشت گردی کی لہر تا حال برقرار ہے۔ یہ افغان جنگ تقریباً پندرہ سال تک جاری رہی۔ نتیجتاً، سوویت یونین کو شکست ہوئی اور وہ سمٹ کر رُوس تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ایسی ہی خُوں ریز جنگ میں رُوسی صدر، پیوٹن نے اپنے سابق شامی ہم منصب، بشارالاسد کی حمایت کی، وہاں دو سال تک شدید بم باری کی اور گیارہ سال تک کیلئے پورے مشرقِ وسطیٰ کو دشمنی کی آگ میں جھونک دیا۔

بدقسمتی سے ہمارے مُلک میں غزہ اور ایران کی جنگیں تو سب کو یاد ہیں، لیکن کسی کو وہ پانچ لاکھ سے زائد شامی شہری یاد نہیں کہ جنہیں رُوس، ایران اور اس کی ملیشیاز نے مل کر ہلاک کیا۔ دوسری جانب یوروپ میں تارکینِ وطن کا سیلاب آ گیا اور اب وہاں مسلمان تارکینِ وطن کے خلاف باقاعدہ مُہم شروع ہو چُکی ہے اور ان سے نفرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب شامی جنگ ہی کا شاخسانہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شام میں پانچ لاکھ سے زائد شہریوں کے قاتلوں اور ایک کروڑ افراد کو بے گھر کرنے والوں کے خلاف کسی بین الاقوامی کریمنل کورٹ میں کوئی مقدمہ نہیں چلا اور اس خانہ جنگی کے کرتا دھرتا نہایت آرام و سکون سے اپنے خاندان اور دولت کے ساتھ رُوس کی مہمان نوازی کا لُطف اُٹھا رہے ہیں۔ گرچہ ''انرجی سیز فائر'' کچھ پیچیدگیوں کا شکار اور نہایت محدود معاہدہ ہے، لیکن یہ جنگ بندی کی شروعات کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ نیٹو کے مقبوضہ علاقوں، یوکرین کی سلامتی اور مستقل امن کا احاطہ نہیں کرتا۔ ایسے میں یوکرین کیلئے لازم ہے کہ وہ بین الاقوامی سلامتی کی ضمانتیں حاصل کرے کیونکہ اگر وہ اس ضمن میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر رُوس کے خلاف جنگ میں اسے ملنے والی کام یابیاں رائیگاں جائیں گی اور رُوس کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی افواج بالخصوص معیشت دوبارہ مستحکم کر سکے۔ یاد رہے، پانچ سال کے طویل عرصے سے جاری جنگ کسی بڑی عالمی طاقت کیلئے بھی ایک دلدل سے کم نہیں ہوتی۔ گرچہ رُوس آبادی اور وسائل کے اعتبار سے ایک بڑا مُلک ہے، لیکن ہے تو یورپ کے خطّے میں اور وہ اتنے طویل عرصے تک اپنے پڑوسیوں کی دُشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے توانائی کے زیادہ تر وسائل یورپ میں فروخت ہوتے ہیں اور اگر یورپ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو کیا پھر ماسکو ہمیشہ کیلئے عالمی مارکیٹ سے 35 فیصد کم ریٹ پر تیل فروخت کر کے اپنے عوام کا معیارِ زندگی برقرار رکھ سکے گا؟

کیا عوام کی ناراضی کی صُورت میں اُسے گزشتہ صدی کی افراتفری کی صُورتِ حال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا رُوس اپنے عوام کو وہ معیارِ زندگی دے سکے گا، جو یورپ کے عوام کو میسّر ہے، جو اس کا پڑوسی ہے۔ یاد رہے، اس سے قبل بھی سوویت یونین بکھرنے کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ پہلی افغان جنگ اور یورپ میں واقع سوویت ریاستوں میں بغاوت کے بعد سوویت یونین دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اس بات کو بھی مدِنظر رکھنا ضروری ہے کہ یوکرین جنگ میں فریقین کا بے تحاشا جانی و مالی نقصان ہوا۔ پانچ سال سے جاری اس جنگ کے دوران مجموعی ہلاکتوں کی تعداد سوا چھے لاکھ سے زائد ہو چُکی ہے۔ اگر غور کیا جائے، تو شام، یمن، ایران، غزہ یا کسی بھی جنگ میں حالیہ برسوں میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔

یوکرین نسبتاً چھوٹا مُلک ہے اور اسی وجہ سے وہاں ہلاکتیں بھی کم ہوئیں جبکہ رُوس میں زیادہ ہلاکتوں کے سبب نہ صرف اس کے عالمی طاقت کے تاثر کو نقصان پہنچا بلکہ وہ عالمی اسٹیج پر اپنا موثر کردار ادا کرنے سے بھی قاصر رہا اور اس کا اندازہ حالیہ ایران جنگ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں رُوس بیانات تو بہت دیتا رہا لیکن نہ تو وہ امریکی پابندیوں سے صرفِ نظر کر کے ایران کی کوئی ٹھوس مدد کر سکا اور نہ ہی سفارتی سطح پر کوئی غیر معمولی پیش رفت۔ اس سے یقیناً ایران کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوگی اور اسے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ کیا آئندہ ر

सम्पादकीय

ऐसी संसद का औचित्य

हम आपको 20 अगस्त, 2010 का एक घटनाक्रम बताते हैं। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थीं। उस दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन सरकार के समर्थक दलों के 60 से अधिक सांसद लोकसभा हॉल में ही मौजूद थे। उनमें सपा के मुलायम सिंह यादव, राजद के लालू प्रसाद यादव, जनता दल-यू के शरद यादव समेत उन सांसदों ने एक 'नकली संसद' का आयोजन किया। अंग्रेजी में इसे 'मॉक पार्लियामेंट' कहते हैं। उसकी कृत्रिम कार्यवाही के मद्देनजर लालू यादव को 'प्रधानमंत्री' बनाया गया और वे सभी सांसद 'ट्रेजरी सीटों' पर बैठ गए। दिलचस्प यह है कि तत्कालीन भाजपा संसदीय दल के उपनेता गोपीनाथ मुंडे को 'कृत्रिम स्पीकर' की भूमिका दी गई। यह दीगर है कि पार्टी आलाकमान ने उन हरकतों के लिए मुंडे को खूब फटकार लगाई। कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उस 'नकली संसद' का आयोजन कैबिनेट द्वारा पारित किए गए सांसद वेतन, भत्ते आदि के बिल और 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया' बिल के विरोध में किया गया था। यह ड्रामा करने वाले सांसद चाहते थे कि उनका वेतन ज्यादा बढ़ाया जाए। बहरहाल तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार को जब उस नाटक की जानकारी मिली, तो उन्होंने 'नकली संसद' के आयोजकों को फटकार लगाई, निराशा व्यक्त की और उसे 'असंसदीय' तथा 'असंवैधानिक' आचरण करार दिया। आज उसी मीरा कुमार ने 'एक और नकली संसद' की अध्यक्षता की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग के 'जन-संस्करण' पर चर्चा तय की गई थी। यह 'नकली संसद' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर आयोजित की गई। यदि 2010 का आचरण और आयोजन 'असंसदीय' और 'असंवैधानिक' था, तो कांग्रेस का यह नाटक भी गलत और आपत्तिजनक है। क्या मौजूदा स्पीकर ओम बिरला कांग्रेस नेता से स्पष्टीकरण मांगेंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस संदर्भ में 'असंसदीय' करार दिए जा सकते हैं? बेशक कांग्रेस का यह प्रयास कुंठित और निराशाजनक है, क्योंकि संसद का 'नकली संस्करण' पेश नहीं किया जा सकता। संसद सड़क पर नहीं लाई जा सकती। पहले यह आयोजन 'अशोका होटल' में किया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। बेशक सीईसी या किसी अन्य संवैधानिक पदासीन व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाने को कांग्रेस और विपक्ष स्वतंत्र हैं। उन्हें संसदीय अधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति (देश के उपराष्ट्रपति) को भी विशेषाधिकार हैं कि वे ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करें या उन्हें खारिज कर दें। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी साल मार्च-अप्रैल में भी कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के दलों ने सीईसी के ही खिलाफ 'महाभियोग' प्रस्ताव के नोटिस दिए थे। जितने सांसदों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, उनसे अधिक ही दस्तखत कराए गए थे, लेकिन उन नोटिसों और प्रस्ताव को 'विचारणीय' नहीं माना गया, लिहाजा खारिज कर दिए गए।

चक्रवातों के साये में तटीय भारत का भविष्य



डॉ. प्रियंका सौरभ

चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बचता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें और नदियों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है।

समुद्र जितना जीवनदायी है, उसका रौद्र रूप उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बेहद अहम है। लेकिन यही तटीय क्षेत्र हर साल चक्रवातों, समुद्री तूफानों, बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा भी झेलते हैं। चक्रवात अर्नब ने एक बार फिर तटीय भारत की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि चक्रवात कब और कहां आएगा, बल्कि यह भी है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बदलते मौसम के दौर में अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से नुकसान कम करने की रणनीति बनानी होगी। चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बचता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें और नदियों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। तटीय क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा भी बड़ी समस्या है। चक्रवात के दौरान बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संचार सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। इससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। कई तटीय शहरों में अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निचले इलाकों में बस्तियों का विस्तार खतरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को बचाने के साथ-साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन

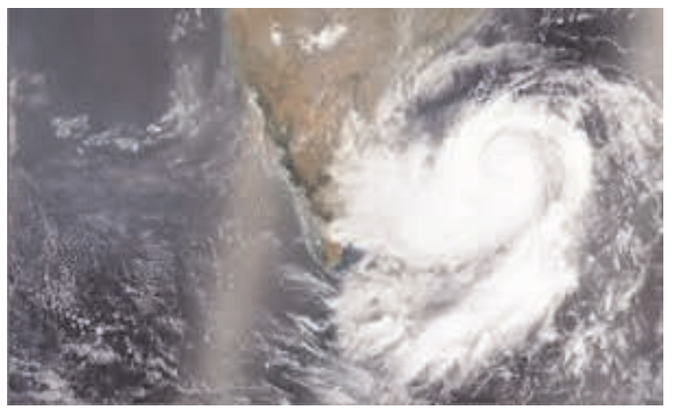

जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली पहले से बेहतर हुई है, लेकिन चुनौती अब भी यह है कि चेतावनी समय पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों, दूरदराज के गांवों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों तक सूचना पहुंचाना आसान नहीं है। कई बार लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते या घर और आजीविका छोड़ने के डर से सुरक्षित स्थानों पर जाने में देरी करते हैं। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को उसके खतरे और उससे बचने के उपायों के बारे में समझाना भी जरूरी है। चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की चिंता सताती है। चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी भर जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कमजोर होना भी चिंता का विषय है। मैंग्रोव वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों का विनाश और समुद्र तटों पर बढ़ता निर्माण चक्रवातों के खतरे को बढ़ाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री लहरों की ताकत कम करने और तटीय इलाकों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा। मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ उपग्रहों, डॉप्लर रडार और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार जरूरी है। चेतावनी केवल मोबाइल संदेशों तक सीमित न रहे। सायरन, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। चेतावनी स्थानीय भाषा में हो और उसमें यह साफ बताया जाए कि लोगों को क्या करना है और कहां जाना है। इसके साथ ही तटीय इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। चक्रवात आश्रयस्थलों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित निकासी मार्ग बनाने और अस्पतालों, बिजलीघरों तथा पेयजल व्यवस्था को आपदा के लिहाज से मजबूत करने की जरूरत है। आश्रयस्थलों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नियमित मॉक ड्रिल से लोगों को आपदा के समय सही कदम उठाने का अभ्यास कराया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, मछुआरा समितियों और युवाओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूलों में आपदा संबंधी जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए। स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के जोखिम की बेहतर जानकारी होती है। इसलिए उनकी भागीदारी से राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी नुकसान कम किया जा सकता है। मैंग्रोव वनों, आर्द्रभूमियों और तटीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगे और तटीय विनियमन के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा मछुआरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बीमा, आर्थिक सहायता और आजीविका पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है, ताकि आपदा के बाद वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।चक्रवात अर्नब ने यह समझने का अवसर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन बेहतर तैयारी से उनके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। भारत ने मौसम पूर्वानुमान और लोगों की निकासी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब जरूरत राहत और बचाव तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो आपदा से पहले ही नुकसान को कम कर सके।

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)

नौजवानों को निगलता नशे का ज़हर



संजीव ठाकुर

स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, मन का बल बढ़ाए और मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा कर दे, नशा शिक्षा, चरित्र और आत्मबल तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संवेदना और बचपन की मासूमियत है। संवेदना मनुष्य को मनुष्य बनाती है और बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव रखता है। किंतु आज नशीले पदार्थों का बढ़ता जाल इन दोनों पर सबसे कड़ा प्रहार कर रहा है। नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि विवेक, करुणा, परिवार, शिक्षा, संस्कृति और भविष्य को भी नष्ट कर देता है। जिस आयु में बच्चों के हाथों में पुस्तकें और सपने होने चाहिए, वहाँ यदि नशे का जहर पहुँच जाए तो आने वाला पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स, सिंथेटिक नशे, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम तथा नशीली गोलियों का प्रसार चिंताजनक रूप से बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार देश में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। 2019 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग शराब, 3 करोड़ से अधिक लोग भांग या गांजा तथा लगभग 2.3 करोड़ लोग ओपिओइड (अफीम, हेरोइन आदि) का सेवन करते पाए गए। इनमें बड़ी संख्या 10 से 17 वर्ष और 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में पंजाब, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा गोवा प्रमुख हैं। पंजाब में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का गंभीर संकट लंबे समय से चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पार से होने वाली तस्करी ने युवाओं को प्रभावित किया है। राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ी है। महानगरों में नशीली गोलियां, कोकीन और पार्टी ड्रग्स तेजी से फैल रहे हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि नशे की शुरुआत अब किशोरावस्था में ही होने लगी है। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, गलत संगति तथा मानसिक तनाव के कारण अनेक बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। परिणामस्वरूप पढ़ाई छूट जाती है, अपराध बढ़ते हैं, हिंसा और आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। नशा सबसे पहले मनुष्य की संवेदना को समाप्त करता है। जो व्यक्ति कभी माता-पिता के प्रति श्रद्धावान था, वही नशे की लत में उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। परिवार की जमा पूंजी नशे में समाप्त हो जाती है। अनेक युवा चोरी, लूट और अन्य अपराधों की ओर बढ़ जाते हैं। धीरे-धीरे रिश्तों की गर्माहट समाप्त होने लगती है और मनुष्य केवल नशे का दास बनकर रह जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था शराब और नशा मनुष्य की आत्मा का पतन कर देते हैं। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का संदेश था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश नशामुक्त समाज की स्थापना के लिए भी उतना ही आवश्यक है। नशे के विरुद्ध केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, धार्मिक संस्थाएँ, मीडिया तथा शासन सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना, खेल, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना, विद्यालयों में नशामुक्ति शिक्षा को अनिवार्य बनाना तथा नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था करना समय की आवश्यकता है। सीमाओं पर तस्करी रोकने के साथ-साथ ऑनलाइन अवैध नेटवर्क पर भी कठोर कार्रवाई आवश्यक है। यदि किसी राष्ट्र का बचपन सुरक्षित है तो उसका भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन यदि बचपन नशे की गिरफ्त में चला गया, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल आर्थिक ही नहीं, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी कमजोर हो जाएँगी। इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है। आइए संकल्प लें कि हम अपने घर, विद्यालय, समाज और कार्यस्थल पर नशामुक्ति का संदेश फैलाएँगे। हर बच्चे के हाथ में नशा नहीं, पुस्तक होगी; हर युवा की आँखों में धुंध नहीं, सपने होंगे; और हर परिवार में भय नहीं, संवेदना और विश्वास का वातावरण होगा। यही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की वास्तविक पहचान बनेगी। वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में नशीले पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल संरक्षण का गंभीर संकट बन चुकी है। गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार नशे की तस्करी पर लगातार कार्रवाई के बावजूद इसकी पहुँच बच्चों और युवाओं तक बढ़ रही है।

(यह लेखक के अपने निजी विचार है)





जयपुर में 'समवेद ज्वेल्स' का भव्य शुभारंभः

बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने किया नए शोरूम का उद्घाटन



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। देश के प्रतिष्ठित और उभरते आभूषण ब्रांडों में अपनी खास पहचान बनाने की ओर अग्रसर 'समवेद ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड' (Samved Jewels Pvt. Ltd.) ने आज गुलाबी नगरी जयपुर में अपने नए और भव्य ज्वेलरी शोरूम का शानदार शुभारंभ किया. इस खास उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि और ब्रांड एंबेसडर के रूप में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत शामिल हुईं। उन्होंने फीता काटकर शोरूम का औपचारिक उद्घाटन किया।

मल्लिका शेरावत की मौजूदगी से शोरूम की बढी रौनक

भव्य उद्घाटन समारोह का शुभारंभ आज 1 नवंबर 2026 को सुबह ठीक 11:15 बजे हुआ। जैसे ही बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं, प्रशंसकों और मेहमानों की भारी भीड़ ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। शोरूम के कलेक्शन और डिजाइन की तारीफ करते हुए मल्लिका शेरावत ने कहा कि समवेद ज्वेल्स का यह नया प्रतिष्ठान जयपुर के लोगों के लिए शुद्धता, अद्वितीय कारीगरी और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम साबित होगा।

अत्याधुनिक और विशेष आभूषणों का संग्रह

समवेद ज्वेल्स का यह नया शोरूम ग्राहकों को आभूषण खरीदारी का एक विश्वस्तरीय और लग्जरी अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पारंपरिक राजस्थानी कुंदन-मीनाकारी, पोल्की, एंटीक गोल्ड से लेकर समकालीन डायमंड ज्वेलरी का एक बेहद खूबसूरत और विशाल कलेक्शन उपलब्ध कराया गया है। ब्रांड का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतरीन गुणवत्ता और भरोसे के साथ हर अवसर के लिए सबसे अनोखे आभूषण पेश करना है। उद्घाटन के इस खास मौके पर समवेद ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कई वरिष्ठ अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक और आभूषण जगत के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस नई शुरुआत के लिए पूरी टीम को बधाई दी।

गहलोत और जूली ने रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक, कहा- तानाशाही मानसिकता के खिलाफ एकजुट है देश



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर/नई दिल्ली। SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतिहासिक करार दिया है. दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक रैली न कभी पहले हुई है और न भविष्य में होगी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रामलीला मैदान में आज की रैली ने इतिहास रच दिया. जैसी रैली आज दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की हुई है, वह 'न भूतो न भविष्यति' वाली बात है, जहां तक नजर जाती थी, वहां जनसमूह ही दिखाई दे रहा था. जनता में इतना उत्साह, अनुशासन और धैर्य था, और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्पित था. अशोक गहलोत का केंद्र पर हमलाः पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह रैली आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ा संकेत है कि पूरा भारत-चाहे युवा हों, किसान हों, व्यवसायी हों, मध्यम वर्ग हो या दलित हों, समाज के हर वर्ग के लोग अपने वोट की रक्षा के लिए इन फासीवादी और तानाशाही मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एकजुट हैं. इस ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए वे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं राजस्थान समेत देशभर से रैली में आए सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन का हृदय से धन्यवाद देता हूं. आज की रैली से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, वह देश से वोट का अधिकार खत्म नहीं कर सकती. यह वोट चोरी अब चलने वाली नहीं है।

लोकतंत्र बचाने का शंखनाद

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह रैली वोट चोरी और इसके सूत्रधारों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश की जनता के आक्रोश का शंखनाद है. आज रामलीला मैदान से उठी आवाज ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार और लोकतंत्र पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी. जूली ने कहा कि रामलीला मैदान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है. यह मैदान इस बात का भी प्रतीक है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है. राहुल गांधी जिस तरह कहते हैं कि यह 'शिव की बारात' है, आज रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब उसी भावना का प्रतीक नजर आया. जूली ने कहा कि रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि देश की जनता अब अपने वोट के अधिकार पर किसी भी तरह का हमला स्वीकार करने को तैयार नहीं है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठी यह आवाज अब देश के हर कोने तक पहुंचेगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग

जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह जनता के वोट के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष और देश का आमजन एकजुट होकर आवाज उठा रहा है. वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास अपने पद पर बने रहने का अब कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है. उन्हें तुरंत पद छोड़ना चाहिए. देश की जनता का स्पष्ट संदेश है कि वोट चोरों को गद्दी छोड़नी होगी.

जूली ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्षता से चुनाव कराना है, ताकि जनता की भावना के अनुरूप उसके प्रतिनिधि चुने जा सकें, लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है. मनमाने तरीके से मतदाता सूचियों से नाम हटाने और जोड़ने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं. जब मतदाता के वोट पर ही सवाल खड़े होने लगें, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहे और हर व्यक्ति बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके.

ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के प्रथम दिवस पर जयपुर वन मण्डल में 95 गतिविधियाँ आयोजित

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। राज्य सरकार द्वारा मिशन लाइफ के अंतर्गत दिनांक 01 से 07 नवम्बर 2026 तक आयोजित किए जा रहे ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के प्रथम दिवस रविवार को जयपुर वन मण्डल के अंतर्गत विभिन्न वन क्षेत्रों, रेंज कार्यालयों, नाकों एवं पौधशालाओं में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की थीम पर विभिन्न जागरूकता एवं जनभागीदारी संबंधी गतिविधियों का आयोजित की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ जयपुर सिटी रेंज स्थित स्मृति वन में योग सत्र एवं वॉकाथोन के आयोजन के साथ किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लेकर नियमित व्यायाम, शारीरिक सक्रियता एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में योग, व्यायाम एवं पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न रेंज कार्यालयों में मिशन लाइफ की पर्यावरण संरक्षण संबंधी शपथ (मिशन लाइफ प्लेज), कार्यालय परिसर में साफ-सफाई तथा पौधारोपण जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं विभिन्न वन नाकों एवं पौधशालाओं में भी पौधशाला परिसर की साफ-सफाई, पौधों की देखभाल, पौधारोपण एवं मिशन लाइफ की शपथ सहित विभिन्न 95 गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमे कुल लगभग 474 प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं विभिन्न कार्यालयों में वृक्षारोपण गतिविधि के अंतर्गत कुल 100 पौधे रोपित किए जाकर पौधारोपण एवं हरितीकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई एवं साथ ही प्रतिभागियों को रोपित पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया गया। जिला उप वन संरक्षक राहुल झांझड़िया ने बताया कि जयपुर वन मण्डल द्वारा मिशन लाइफ के उद्देश्यों के अनुरूप आमजन एवं विभागीय कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगामी दिवसों में भी निर्धारित थीम के अनुसार विभिन्न जन-जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण के लिए मतदान दल 02 नवंबर सोमवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद होंगे रवाना

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर का दौरा कर मतदान दलों की रवानगी एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

पांच पंचायत समितियों के 442 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल होंगे रवाना

3 नवंबर को जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य तथा 5 नवंबर को पंच-सरपंच पदों के लिए होगा मतदान

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने रविवार को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड परिसर का दौरा कर तृतीय चरण के मतदान दलों की रवानगी एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री वितरण, वाहन पार्किंग तथा मतदान दलों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने तथा मतदान दलों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जयपुर जिले में तृतीय चरण के मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके लिए सोमवार, 2 नवंबर को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया, ईवीएम के संचालन, बैलेट पेपर तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण के तहत जिला परिषद के वार्ड संख्या 27 से 37, जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी एवं सांगानेर में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इस चरण में चाकसू पंचायत समिति के 17 पंचायत समिति वार्ड और 32 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, कोटखावदा के 15 पंचायत समिति वाड और 27 ग्राम पंचायतों के लिए 82 मतदान केंद्र, माधोराजपुरा के 15 पंचायत समिति वार्ड और 25 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, फागी के 15 पंचायत समिति वार्ड और 26 ग्राम पंचायतों के लिए 90 मतदान केंद्र तथा सांगानेर के 15 पंचायत समिति वार्ड और 23 ग्राम पंचायतों के लिए 84 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कुल 3 लाख 74 हजार 816 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1 लाख 93 हजार 206 पुरुष, 1 लाख 81 हजार 609 महिला तथा एक अन्य मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण के तहत जिला परिषद के वार्ड संख्या 27 से 37 तथा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मंगलवार, 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पंच एवं सरपंच पदों के लिए बुधवार, 4 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद गुरुवार, 5 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच पद के लिए शुक्रवार, 6 नवंबर को चुनाव आयोजित किया जाएगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर में की जाएगी।

नीता अंबानी ने किया 'नीता मुकेश अंबानी अनंत आश्रय' का भूमिपूजन, 5,000 से अधिक जरूरतमंदों को मिलेगा अपना घर

महाराष्ट्र के कर्जत में 100 एकड़ में बनेगा परिसर, अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलेगा सहारा

घर-परिवार जैसा माहौल, अस्पताल, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं भी होंगी

नीता अंबानी बोलीं: माता-पिता को यह सुकून मिले कि उनके बाद भी बच्चों का अपना घर और परिवार होगा



आवाज़ ए तसनीम

मुंबई। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रविवार को महाराष्ट्र के कर्जत में 'नीता मुकेश अंबानी अनंत आश्रय' का भूमिपूजन किया। करीब 100 एकड़ में बनने वाला यह परिसर 5,000 से अधिक अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर-परिवार जैसा माहौल और देखभाल उपलब्ध कराएगा। भूमिपूजन में ईशा अंबानी भी शामिल हुईं। रिलायंस फाउंडेशन की इस गैर-लाभकारी पहल को आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। भूमिपूजन के अवसर पर नीता अंबानी ने कहा कि अनंत आश्रय उनके और उनके परिवार के दिल के बेहद करीब है। उन्होंने कहा, 'एक मां के तौर पर मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि जिन माता-पिता को जीवनभर यह चिंता रही है कि उनके न रहने पर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उन्हें यह भरोसा मिल सके कि उनके बच्चे का हमेशा अपना घर और परिवार होगा।' उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां हर उम्र के व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और हर नए दिन की ओर उम्मीद से देखने का अवसर मिलेगा। अनंत आश्रय की परिकल्पना केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि ऐसे समुदाय के रूप में की गई है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन मिले। परिसर में परिवार जैसे छोटे-छोटे घर होंगे, जहां विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारी देखभाल करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की योजना तैयार होगी। यहां रहने वालों, चिकित्सा विशेषज्ञों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलाकर करीब 15 हजार लोगों का समुदाय विकसित होने की उम्मीद है। प्रस्तावित परिसर में विशेष अस्पताल, पुनर्वास केंद्र, फिजियोथेरेपी और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ शिक्षा, खेल, संगीत और कला के अवसर भी मिलेंगे। बेकरी, कैफे और हस्तशिल्प केंद्रों के जरिए रोजगार और कौशल विकास की व्यवस्था होगी। परिसर में मंदिर, बगीचे और वनतारा के सहयोग से पशुओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने वाला फार्म भी प्रस्तावित है। आसपास के गांवों के लोग भी यहां की कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। खास बात यह है कि नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन पर इस पहल की नींव रखी। अपने संबोधन में उन्होंने इसे भारत मां के चरणों में एक मां की ओर से छोटी-सी भेंट बताया।

सतत जीवनशैली एवं स्वच्छ पर्यावरण का संदेश लेकर जयपुर में आयोजित हुई 'साइक्लोथॉन फॉर ऑल'

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिखाई हरित भविष्य की राह, सचिव पर्यावरण शैलजा देवल ने प्रतिभागियों को वितरित किए प्रमाण-पत्र

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु एवं सतत जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रविवार को जयपुर में 'ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक' के शुभारंभ के क्रम में 'साइक्लोथॉन फॉर ऑल' का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण विभाग एवं इंटरनेशनल सोसायटी फॉर लाइफ साइंसेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस साइक्लोथॉन में बड़ी संख्या में साइकिल प्रेमियों, युवाओं एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती शैलजा देवल तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। हमें अपनी जीवनशैली में ऐसे छोटे-छोटे बदलाव अपनाने होंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें। साइकिल चलाना केवल परिवहन का एक विकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ वायु और पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए, तो सतत विकास का लक्ष्य हासिल करना संभव है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साइकिलिंग जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसहभागिता और व्यवहार परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण हैं। साइक्लोथॉन जैसे आयोजन लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने तथा सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी दिनचर्या में पर्यावरण अनुकूल आदतों को शामिल करना चाहिए।

पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती शैलजा देवल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तभी व्यापक और प्रभावी बन सकते हैं, जब प्रत्येक नागरिक अपनी दिनचर्या में पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाए। साइकिलिंग जैसे सरल एवं व्यवहारिक विकल्प न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं, बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी यह दर्शाती है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस आयोजन से मिले संदेश को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और अन्य लोगों को भी सतत जीवनशैली के लिए प्रेरित करें।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा सतत जीवनशैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के समापन पर सचिव पर्यावरण श्रीमती शैलजा देवल ने साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

साइक्लोथॉन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल परिसर से प्रारंभ होकर मालवीय नगर स्थित एपेक्स सर्किल के रास्ते नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय तक आयोजित की गई। इसमें प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाकर स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ राजस्थान का संदेश दिया। प्रतिभागी के रूप में शामिल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक हेमंत सिंह ने इस अवसर पर कुल 60 किलोमीटर साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में आम नागरिक की भूमिका का प्रेरक संदेश दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को निजी वाहनों के स्थान पर साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा।

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के अंतर्गत आयोजित यह पहल पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

دہلی میں انڈیا اتحاد کی عظیم الشان ریالی
مودی، شاہ اور سے جمہوریت کو خطرہ: راہول گاندھی



آواز تسنیم

کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ ہندوستان میں کئی برسوں سے ووٹوں کی چوری ہورہی ہے اور انتخابی عمل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین (ای وی ایم) کے علاوہ ووٹرلسٹوں میں ردوبدل کرکے بھی دھاندلی کی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد ووٹر لسٹوں سے 11.53 کروڑ نام ہٹائے گئے، جو مجموعی ووٹروں کا تقریباً 15 فیصد ہیں۔ راہول گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عہدے سے ہٹنا ہوگا اور جیل جانا پڑے گا۔ رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلی کے ذریعے عوام نے وزیراعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت یا رہنما کی آواز نہیں بلکہ ملک کے نوجوانوں، کسانوں اور مزدوروں کی مشترکہ آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت اور آئین کو ختم نہیں ہونے دیا جائے گا اور دولت یا طاقت رکھنے والا کوئی شخص آئین سے بڑا نہیں ہوسکتا۔ انتخابی بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ مدھیہ پردیش، ہریانہ، چھتیس گڑھ، مہاراشٹرا، کرناٹک اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹوں کی چوری ہوئی۔ ان کے مطابق ووٹرلسٹوں سے نام ہٹانے اور نئے نام شامل کرنے کے ذریعے بھی انتخابی عمل کو متاثر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں این ڈی اے اور اپوزیشن کے درمیان ووٹوں کا فرق تقریباً 3 فیصد تھا جبکہ اس کے بعد 15 فیصد ووٹروں کے نام فہرستوں سے ہٹائے گئے۔ راہول گاندھی نے اس پورے معاملے کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پر عائد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کے بغیر نہ نریندر مودی وزیراعظم بن سکتے تھے اور نہ امت شاہ وزیر داخلہ بن سکتے تھے۔ راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس نے تعلیم، صحت، سی بی آئی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، عدلیہ، بیوروکریسی اور پولیس سمیت ملک کے مختلف آئینی و انتظامی اداروں پر اپنا کنٹرول قائم کرلیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس صورت حال کا نقصان نوجوانوں، کسانوں اور چھوٹے تاجروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ معاشی عدم مساوات پر بات کرتے ہوئے راہول گاندھی نے الزام لگایا کہ ملک کے وسائل چند صنعت کاروں، خصوصاً اڈانی اور امبانی کے حوالے کیے جارہے ہیں۔ ان کے مطابق بڑے صنعت کاروں کے لاکھوں کروڑ روپے کے قرض معاف کردیے جاتے ہیں جبکہ کسان، مزدور یا چھوٹا تاجر قرض ادا نہ کرپائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا ہندوستان چاہیے جہاں کسان کو اس کی محنت کا پورا پھل ملے اور 18 گھنٹے پڑھنے والے طالب علم کو تعلیم اور روزگار کے مواقع حاصل ہوں۔ انہوں نے 'شیو کی بارات' کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر طبقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں جگہ ملے۔ راہول گاندھی نے حکمراں جماعت کو خبردار کیا کہ گیانیش کمار کے بعد وہ مودی اور امت شاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے اور ووٹوں کی چوری اور ملک کے وسائل فروخت کرنے کے الزامات پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں، نہ مودی سے، نہ امت شاہ سے اور نہ گیانیش کمار سے۔ وہ نفرت یا تشدد کے بجائے مہاتما گاندھی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان کے مطابق یہ احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت کی لڑائی نہیں بلکہ آئین اور جمہوریت کے تحفظ کی مشترکہ تحریک ہے۔

☆☆☆

بی جے پی نے کناٹ پلیس کی تمام دکانیں زبردستی بند کرائی ہیں: راہل گاندھی



آواز تسنیم: دہلی میں انڈیا بلاک کی عظیم الشان ریلی کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ اس دوران لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رہنما راہول گاندھی نے بی جے پی پر بڑا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دہلی کے کناٹ پلیس میں بی جے پی نے زبردستی تمام دکانیں بند کرادی ہیں۔ راہول گاندھی نے سوال اٹھایا کہ آخر تاجروں کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ رام لیلا میدان میں منعقدہ عظیم الشان ریلی میں شامل ہونے کیلئے کناٹ پلیس سے گزرتے ہوئے راہول گاندھی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ ''ہم نے سب لوگوں سے کہا تھا کہ جب آپ مارچ اور عظیم الشان ریلی میں شرکت کیلئے یہاں آئیں تو چیزیں خریدیں، خریداری کریں۔ لیکن یہاں کناٹ پلیس آتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ بی جے پی نے تمام دکانیں زبردستی بند کرادی ہیں۔ تو آپ جان لیجیے کہ تاجروں کو نقصان کون پہنچا رہا ہے اور یہ سب کیسے ہورہا ہے!''۔ اس سے قبل ہفتہ کی دیررات راہول گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ویڈیو شیئر کر ریلی میں آنے والے لوگوں سے مقامی تاجروں کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ''نمسکار، کل لاکھوں لوگ رام لیلا مارچ کیلئے دہلی آرہے ہیں۔ تہواروں کا موسم ہے۔ دیوالی، چھٹھ اور بھائی دوج کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باہر سے دہلی آنے والے لاکھوں لوگ یہاں کے تاجروں کی مدد کریں۔'' ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ''احتجاج، مارچ اور ریلی کیجیے، ساتھ میں تھوڑی سی خریداری بھی کیجیے، اس سے تاجروں کو فائدہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ریلی سے تاجروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بی جے پی خوف زدہ ہے، اسی لیے افواہیں پھیلا رہی ہے۔ لیکن ہم دونوں کام کریں گے۔ کل مارچ بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی اور لاکھوں لوگ ہمارے تاجروں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں سے سامان بھی خریدیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت پیار۔ دیوالی مبارک۔ جے ہند۔'' انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد ووٹرلسٹوں سے 11.53 کروڑ نام ہٹائے گئے، جو مجموعی ووٹروں کا تقریباً 15 فیصد ہیں۔ راہول گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عہدے سے ہٹنا ہوگا اور جیل جانا پڑے گا۔ رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلی کے ذریعے عوام نے وزیراعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر کو واضح پیغام دے دیا ہے۔

گیانیش کمار کا علامتی 'عوامی مواخذہ'

مودی اور شاہ کی ایما پر کام کرنے والے سی ای سی کو ہٹا دینے پر کانگریس کا زور



آواز تسنیم: انڈیا بلاک میں ہفتہ کے دن چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا علامتی 'عوامی مواخذہ' کیا۔ اُس نے الزام عائد کیا کہ حق رائے دہی خطرے میں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن مودی حکومت کی ایما پر کام کررہا ہے۔ یہ کارروائی لوک سبھا کی سابق اسپیکر میرا کمار کی صدارت میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے سرکاری بنگلہ میں ہوئی ۔انڈیا بلاک قائدین ، ارکان پارلیمنٹ ، سیول سوسائٹی کے نمائندے اور بعض افراد نے اس میں حصہ لیا جن کے نام فہرست رائے دہندگان سے کاٹ دیئے گئے ۔کانگریس نے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے مطالبہ پر زور دینے کیلئے قومی دارالحکومت میں اپوزیشن کی اتوار کی ریالی کی دھن طئے کردی ۔تحریک پیش کرتے ہوئے کھرگے نے چیف الیکشن کمشنر پر غداری کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے سی ای سی کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے اور اُنہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے 2023 کا الیکشن کمشنرس کے تقرر کا قانون رد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایس آئی آر کو ختم کردینے کی بھی مانگ کی ۔ قائد اپوزیشن راجیہ سبھا نے الزام عائد کیا کہ گیانیش کمار وزیراعظم مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی ہدایت پر الیکشن کمشنر کو چلا رہے ہیں۔ کھرگے نے کہا کہ آج حق رائے دہی خطرے میں ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار مودی اور شاہ کے کہنے پر کمیشن کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے انہیں ہٹانے کیلئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تجاویز رکھی تھیں لیکن اُن کی نوٹسوں کو مسترد کردیا گیا۔ عوامی مواخذہ کیلئے لوک سبھا جیسا سیٹ اپ قائم کیا گیا۔ پہلی تین صفو ں میں مائیکروفون لگائے گئے تھے۔ یہ پروگرام اصل میں جمعہ کو ہونا تھا لیکن دہلی میں بارش کی وجہ سے اسے ایک دن کیلئے آگے بڑھا دیا گیا تھا۔ کارروائی شروع کرتے ہوئے میرا کمار نے کہا کہ یہ اجلاس چیف الیکشن کمشنر کے عوامی مواخذہ کیلئے منعقد کیا جارہا ہے کیونکہ سی ای سی نے غلط طور پر کئی اہل رائے دہندوں کے نام کاٹ دیئے ۔ انڈیا بلاک نے جب یہ مسئلہ اٹھایا تو کوئی جواب دہی طئے نہیں کی گئی لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ انڈیا بلاک ایک میٹنگ طلب کرے گا اور گیانیش کمار کو ہٹانے کی تجویز پیش کرے گا۔ کھرگے نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت نے اقتدار میں جمع رہنے کیلئے سنسد چوری، پارٹی چوری اور اب ووٹ چوری کی ۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک میں جمہوریت ختم کرنے کی کوشش کررہی ہے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ انڈیا بلاک نے اتوار کے دن دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ بچاؤ دیش بچاؤ کے بیانر تلے ریالی کا اعلان کیا ہے۔

ہندوستان کی نیویگیشن خودمختاری مضبوط ہوگی: نریندر مودی

NVS-03 سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر وزیراعظم اور دیگر بی جے پی قائدین کا اظہارِ مسرت

آواز تسنیم: وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتہ کے روز ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے (اسرو) کے سائنس دانوں اور انجینئروں کو اگلی نسل کے نیویگیشن سیٹلائٹ این وی ایس۔ 03 کو لے جانے والے جی ایس ایل وی-ایف 18 راکٹ کی کامیاب لانچنگ پر مبارک باد دی۔ انہوں نے اس مشن کو ہندوستان کے مقامی سیٹلائٹ نیویگیشن نظام 'ناوِک' کو مضبوط بنانے اور اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خود انحصاری حاصل کرنے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں مودی نے کہا کہ اس مشن کی کامیابی ہندوستان کے خلائی سائنس دانوں کی لگن اور تکنیکی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا ''این وی ایس 03- کو لے جانے والے جی ایس ایل وی-ایف 18 کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کے ہمارے سائنس دانوں اور انجینئروں کو مبارک باد۔'' وزیراعظم نے کہا ''یہ مشن ہمارے مقامی سیٹلائٹ نیویگیشن نظام ناوِک کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ جدید صلاحیتوں سے لیس این وی ایس۔ 03 اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خود انحصاری کی ہماری کوششوں کو آگے بڑھائے گا اور ایسی نیویگیشن خدمات کی فراہمی میں مدد کرے گا جن سے ہمارے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ "انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کے خلائی سائنسدانوں کی لگن اور جدت طرازی مسلسل ملک کا سر فخر سے بلند کررہی ہے۔ یہ لانچنگ جمعہ کی رات 11 بج کر 51 منٹ پر آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹہ میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیڈ سے کی گئی۔ جیو سنکرونس سیٹلائٹ لانچ وہیکل (جی ایس ایل وی)-ایف(18) نے 2,232 کلوگرام وزنی سیٹلائٹ این وی ایس 03- کو کامیابی کے ساتھ اس کے مقررہ جیوسنکرونس ٹرانسفر آربٹ (جی ٹی او) میں پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے خلائی پروگرام نے ایک اور اہم کامیابی حاصل کی۔ یہ مشن جی ایس ایل وی کی 20ویں پرواز اور 2026 میں اسرو کی تیسری خلائی لانچنگ تھی۔ تقریباً 50 میٹر بلند تین مرحلوں والے اس لانچ وہیکل نے تقریباً 18 منٹ میں اپنا مشن مکمل کرتے ہوئے نیویگیشن سیٹلائٹ کو مقررہ مدار میں پہنچا دیا۔ این وی ایس 03-اسرو کے اگلی نسل کے نیویگیشن سیٹلائٹ سلسلے کا تیسرا سیٹلائٹ ہے ۔ اسے ہندوستانی علاقائی سیٹلائٹ نیویگیشن نظام (آئی آر این ایس ایس) کی خدمات کو جاری رکھنے، ان کی درستگی بڑھانے اور اعتبار کو بہتر بنانے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے ۔ یہ نظام عام طور پر ناوِک یعنی نیویگیشن وداندین کا نسٹیلیشن کے نام سے مشہور ہے ۔اسی دوران بہار کے چیف منسٹر سمراٹ چودھری نے ہفتہ کو کہا کہ جی ایس ایل وی-ایف 18 کے ذریعے این وی ایس 03-نیویگیشن سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ ہندوستان کی سائنسی صلاحیت، تکنیکی طاقت اور خود انحصاری کی سمت میں ایک اور اہم کامیابی ہے ۔ چودھری نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ''ایکس'' پر جاری اپنے پیغام میں اس قابل فخر کامیابی کے لیے ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم (اسرو) کے تمام سائنس دانوں اور پوری ٹیم کو دلی مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کیں ۔ چودھری نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان خلائی سائنس کے شعبے میں مسلسل نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے ۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہندوستان اپنی سائنسی کامیابیوں کے ذریعے نہ صرف دنیا میں نئی شناخت بنا رہا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے لامحدود امکانات کے دروازے بھی کھول رہا ہے ۔قابل ذکر ہے کہ جی ایس ایل وی-ایف 18 راکٹ کے ذریعے این وی ایس۔ 03 سیٹلائٹ کی لانچنگ 30 اکتوبر 2026 کو رات 11 بج کر 51 منٹ پر سری ہری کوٹا واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے کی گئی۔ این وی ایس۔ 03 ہندوستان کے مقامی سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن نظام 'ناوک ' کی دوسری نسل کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ اس کا مقصد ملک میں سیٹلائٹ پر مبنی سمت، مقام کے تعین اور وقت سے متعلق خدمات کو مزید مضبوط اور قابل اعتماد بنانا ہے ۔ یہ سیٹلائٹ ہندوستان کی خود مختار نیویگیشن صلاحیت کو مضبوط بنانے کے ساتھ نقل وحمل، سمندری سرگرمیوں، ہوابازی اور آفات کے انتظام جیسے شعبوں میں بھی مفید ثابت ہوگا۔

اعظم خان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں



سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان سے متعلق معاملے میں غازی آباد کی پی ایم ایل اے عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اعظم خان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں غازی آباد کی ڈاسنا جیل منتقل کیا گیا۔ اس دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) بھی اعظم خان کو ریمانڈ پر لینے کی تیاری کررہا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے شائع خبر کے مطابق تحقیقاتی ایجنسی اگلے ایک دو دن میں غازی آباد کی پی ایم ایل اے عدالت میں اعظم خان کے ریمانڈ کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ ایجنسی عدالت سے انہیں پولیس حراست میں دینے کا مطالبہ کرے گی۔ اگر عدالت سے ای ڈی کو اعظم خان کی حراستی ریمانڈ مل جاتی ہے تو تحقیقاتی ایجنسی انہیں لکھنؤ لے جاکر پوچھ تاچھ کرے گی۔ فی الحال عدالت نے اعظم خان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو سماعت شروع ہوتے ہی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے عدالت میں اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے اعظم خان کی 14 دن کی حراست کا مطالبہ کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے جوہر یونیورسٹی سے متعلق فنڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں اور رقم کے لین دین کی تفصیلات کے بارے میں بھی عدالت کو آگاہ کیا۔ غازی آباد کی عدالت میں سماعت کے دوران ای ڈی نے اعظم خان کی گرفتاری اور ان سے متعلق مقدمے کی تفصیلات عدالت کے سامنے رکھیں۔ تحقیقاتی ایجنسی نے جوہر یونیورسٹی کی فنڈنگ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے اپنے دلائل پیش کیے۔ ای ڈی نے عدالت کو بتایا کہ جوہر یونیورسٹی سے متعلق فنڈ میں کس طرح کی مبینہ بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تحقیقاتی ایجنسی نے رقم کے لین دین یعنی منی ٹریل سے متعلق معلومات بھی عدالت کے سامنے پیش کیں۔ ای ڈی نے ان حقائق کی بنیاد پر اعظم خان کی 14 دن کی حراست کا مطالبہ کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی آئندہ ایک دو دن میں غازی آباد کی پی ایم ایل اے عدالت میں اعظم خان کے ریمانڈ کیلئے درخواست دے سکتی ہے۔

مودی حکومت کی وداعی قریب، گیانیش کمار کو استعفیٰ دینا ہوگا: کھرگے

آوازِ تسنیم: کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھرگے نے وزیراعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کی وداعی کے دن قریب ہیں اور ہندوستان میں ووٹ چوری کی سازش میں کردار ادا کرنے والے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو استعفیٰ دینا ہوگا اور ان کے خلاف تحقیقات بھی ہوگی۔ مسٹر کھرگے نے اتوار کو یہاں رام لیلا میدان میں اپوزیشن کے 'انڈیا' اتحاد کی 'ووٹ بچاؤ، دیش بچاؤ' مہا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر عوام کی آواز سمجھ لیں، کیونکہ وہ لوگوں کا حق نہیں چھین سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی کی دوسری جنگ ہے اور اپوزیشن اسے جیت کر رہے گا۔ کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ خصوصی جامع نظر ثانی (ایس آئی آر) کے نام پر تقریباً 14 کروڑ ووٹروں کے نام ہٹائے گئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہٹائے گئے ناموں میں کتنے غیر ملکی شہری تھے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چھ ریاستوں میں 10 کروڑ ووٹروں میں صرف 1,600 غیر ملکی ملے ہیں، جن میں زیادہ تر نیپال کے شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی دراندازوں کے نام پر جھوٹ بول رہی ہے اور ووٹر لسٹ میں ردوبدل کا استعمال انتخابی فائدے کے لیے کیا جارہا ہے۔ مسٹر کھرگے نے الزام لگایا کہ مودی حکومت کو مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں اور مزدوروں کے مسائل کی فکر نہیں ہے بلکہ اسے اپنی کرسی کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند مخصوص سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچایا جارہا ہے، جبکہ سرکاری اداروں کی نجکاری سے روزگار اور ریزرویشن پر خطرہ پیدا ہورہا ہے۔ انہوں نے کسانوں کو کم از کم امدادی قیمت (ایم ایس پی) کی قانونی ضمانت دینے کا وعدہ پورا نہ ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹر حکومت منتخب کرتے ہیں لیکن مودی حکومت اپنی پسند کے ووٹر چننے میں لگی ہے۔

سارہ سے لیکر عامر اور سلمان تک ان ستاروں کے خلاف فتویٰ جاری ہوا





بالی ووڈ اداکارہ سارہ علی خان کے کیدارناتھ مندر کے دورے پر تنازعہ کھڑا ہوگیا ہے۔ بریلی میں مقیم مذہبی رہنما اور آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے سارہ علی خان کے مندر جانے کو اسلامی قانون (شریعت) کے تحت غیر قانونی اور حرام قرار دیا۔ رپورٹس کے مطابق سارہ علی خان نے حال ہی میں کیدارناتھ کے مرکزی مندر اور قریبی بھوکنٹ بھیرو مندر میں پوجا اور آرتی میں حصہ لیا۔ مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے کہا کہ 'کسی بھی مسلمان کیلئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کسی دوسرے مذہب میں شامل ہونا، عبادت پڑھنا اور مذہبی رسومات ادا کرنا شریعت کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔' انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا، اگر سارہ علی خان رضاکارانہ طور پر کیدارناتھ مندر میں عبادت کرنے اور آشیرواد حاصل کرنے کیلئے گئیں تو انہوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ ایک حرام فعل ہے۔

عامر خان

بالی ووڈ کے سوپر اسٹار عامر خان نے حال ہی میں اپنی پارٹنر گوری سپراٹ سے شادی کی۔ گوری کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے جبکہ عامر خان مسلمان ہیں۔ شادی کے بعد علی گڑھ کے مسلم پرسنل دارالافتاء کے شاہی مفتی مولانا چوہدری ابراہیم حسین نے ان کی شادی کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے فتویٰ جاری کیا۔

شاہ رخ خان



رپورٹس کے مطابق شاہ رخ خان نے 2013 میں اپنے بچے کی جنس کا ٹسٹ کرایا تھا تاہم شاہ رخ خان نے اس کی تردید کی تھی۔ سروگیسی اور مبینہ قبل از پیدائش جنس کے تعین کے الزامات پر جاری کردہ فتویٰ میں مرکزی دارالافتاء دارگاہ اعلیٰ حضرت نے اسے غیر اسلامی قرار دیا۔ واضح رہے کہ سلمان خان ہر سال گنیش چتورتھی میں حصہ لیتے ہیں۔

سلمان خان

سال 2007 میں سلمان خان نے گنیش پوجا میں شرکت کی اور آرتی کی۔ بریلی میں دارالافتاء منظر اسلام نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیا۔ مزید برآں، 2008 میں سلمان خان نے مادام تساؤ مومی میوزیم میں اپنے موم مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ دارالافتاء کے مفتی سلیم احمد قاسمی نے ان کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں بت پرستی کی ممانعت ہے۔

गाजीपुर में ढाका-टांगाइल हाईवे किया जाम, पुलिस चौकी में भी लगा दी आग

बांग्लादेश में मजदूरों का विद्रोह, वेतन बढ़ाने की मांग पर तोड़फोड़-आगजनी

कम से कम 30,000 टका यानी करीब 23,000 रुपए मासिक वेतन की मांग पर अड़े कर्मी





● ढाका

बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गारमेंट कर्मचारियों ने रविवार को गाजीपुर और राजधानी ढाका में प्रदर्शन किया। गाजीपुर में कर्मियों ने ढाका-टांगाइल हाईवे को जाम कर दिया और कम से कम 30,000 टका यानी करीब 23,000 रुपये मासिक वेतन की मांग की।

प्रदर्शन के बीच सरकार ने नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। गाजीपुर में कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए हाईवे पर प्रदर्शन किया। कालीकैर उपजिला में सफीपुर बाजार, चंद्रा पल्लि बिद्युत, मौचक और तेलीचाला समेत हाईवे के कई हिस्सों पर कर्मचारी लाठी लेकर पहुंच गए। आसपास की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने सुबह अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई।

सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कोनाबारी इलाके में ढाका-टांगाइल हाईवे के बीच बने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। कोनाबारी थाने के प्रभारी अधिकारी इफ्तेखार हुसैन के मुताबिक, इस घटना की जानकारी सामने आई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की पांच प्लाटून भी तैनात की गई। ढाका में भी गारमेंट कर्मचारियों ने मीरपुर-10 चौराहे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मीरपुर के अलग-अलग इलाकों से कर्मचारी रविवार सुबह यहां पहुंचे और चौराहे को जाम कर दिया. इसके कारण मीरपुर-10 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। पुलिस को मौके पर भेजा गया।

गारमेंट उद्योग में कार्यरत है 40 लाख कर्मचारी

बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग में 4,000 पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं और इनमें 40 लाख से ज्यादा कर्मी हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, देश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष 2025-26 में बांग्लादेश से 38.70 अरब डॉलर के गारमेंट का निर्यात हुआ। यहां के कपड़े 150 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं।

सरकार ने बनाया नया वेतन बोर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की. उन्होंने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को 'पूरी गंभीरता' से ले रही है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग के अनुसार नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाया गया है और उम्मीद जताई कि अब कर्मचारी सड़कों से हटकर अपनी फैक्ट्रियों में लौटेंगे।

बढ़ती महंगाई के खिलाफ जर्मनी और फ्रांस में उग्र प्रदर्शन

फ्रैंकफर्ट/पेरिस, आरएनएन। बढ़ती महंगाई और शिक्षा के मुद्दों को लेकर जर्मनी और फ्रांस में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। जर्मनी में हजारों युवाओं के सड़कों पर उतरने के बाद फ्रैंकफर्ट और कोलोन जैसे प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पें और लूटपाट हुई, जिसके चलते पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जर्मनी में युवा-नेतृत्व वाले आंदोलन जेन जी रेगेल्ट ने बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, कोलोन, हैम्बर्ग और म्यूनिख समेत प्रमुख शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए। देश भर में लगभग 1.20 लाख लोग सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन शाम ढलते ही कई शहरों में हिंसक हो गए। फ्रैंकफर्ट में भीषण उपद्रव देखने को मिला, जहां नकाबपोश समूहों ने शहर के मुख्य शॉपिंग इलाके जाइल में दुकानों के शीशे तोड़ दिए और स्टोरों में लूटपाट की। दूसरी ओर, बर्लिन में ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास मुख्य सभा काफी हद तक शांतिपूर्ण रही, हालांकि शहर के अन्य हिस्सों में हुई कई घटनाओं में 27 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए।

घूंघट ओढ़े महिला की मूर्ति ने बनाया नीलामी का रिकॉर्ड



● वियेना

ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संगमरमर की एक मूर्ति 1.925 मिलियन यूरो (20 करोड़ से ज्यादा भारतीय रुपए) में बिकी है। इस नीलामी ने इतालवी बारोक मूर्तिकार एंटोनियो कोराडिनी की कलाकृतियों की बिक्री का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नीलामी घर डोरोथियम ने बताया है कि नीलामी हॉल में मौजूद लोगों के अलावा फोन से जुड़े बोलीदाताओं ने इस बेहद खास मूर्ति को हासिल करने के लिए बढ़-चढ़कर बोलियां लगाईं, जिससे इसकी कीमत एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गई।

20 करोड़ रुपए में बिकी

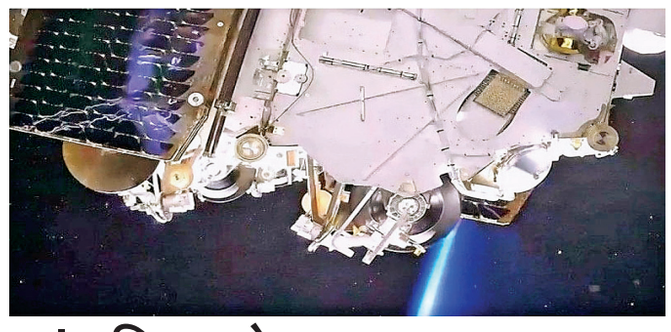

अंतरिक्ष से रूस का दूसरा इंटरनेट सैटेलाइट भी गिरा

● मास्को

रूस अपना खुद का उपग्रह इंटरनेट सिस्टम बना रहा है। इसका नाम रासवेत है। यह स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसा काम करेगा। लेकिन एक बार फिर मुसीबत आ गई। रासवेत-3 नंबर 17 नाम का उपग्रह शुक्रवार 30 अक्टूबर को धरती के वायुमंडल में घुसकर जल गया। यह उपग्रह 19 जुलाई को आसमान में भेजा गया था। तीन महीने भी नहीं गुजरे थे कि यह वापस गिर गया। इससे पहले जून में भी एक ऐसा ही उपग्रह जल चुका था।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उसे विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। खासकर दूर-दराज के इलाकों में अच्छा इंटरनेट पहुंचे। युद्ध और पाबंदियों के समय खुद का सिस्टम होना बहुत जरूरी है। इसलिए रूस कई छोटे उपग्रह आसमान में भेज रहा है जो मिलकर इंटरनेट देंगे. आमतौर पर उपग्रह को पहले थोड़ी नीची ऊंचाई पर भेजते हैं। फिर उसके इंजन से उसे ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यह उपग्रह ऊपर नहीं जा पाया। धीरे-धीरे नीचे आता गया और आखिर में जल गया। जून वाले उपग्रह के साथ भी यही हुआ था।

अच्छी बात यह है कि अभी करीब 30 उपग्रह आसमान में हैं। ज्यादातर 500 किमी की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। पूरा काम रुका नहीं है पर दिक्कतें जरूर आ रही हैं। इतने सारे उपग्रह सही जगह पहुंचाना और लंबे समय तक चलाना आसान नहीं है। एलन मस्क के स्टारलिंक ने हजारों उपग्रह भेजकर यह काम कर दिखाया है। रूस को अभी अनुभव कम है। पाबंदियों की वजह से कुछ जरूरी पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिल रहे होंगे।

पोलैंड संवैधानिक संकट — चरम पर पहुंच गया तनाव

टस्क बोले, कानून के शासन पर कोई डील नहीं

● वारसॉ

पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने टीवी पर प्रसारित संबोधन में देश के गहराते संवैधानिक न्यायाधिकरण संकट पर कड़ा रुख अपनाते हुए है कहा कि हिंसा पर कानून के शासन की जीत होगी। देश की न्यायपालिका को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पोलैंड के संवैधानिक न्यायालय की संरचना को लेकर जारी विवाद ने राष्ट्रपति कारोल नावरोत्स्की के साथ खुला टकराव पैदा कर दिया है।

नए जजों की नियुक्ति को ल गतिरोध के बीच राष्ट्रपति ने संवैधानिक न्यायाधिकरण की इमारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस ने इमारत को घेर लिया। घटनाक्रम का टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ, जिससे यह संकट पोलैंड से बाहर यूरोप की व्यापक राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया। विपक्ष ने टस्क सरकार पर तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह न्यायपालिका में वर्षों से जारी लॉ एंड जस्टिस टीं के हस्तक्षेप के बाद कानून का शासन बहाल करने जरूरी सुधार लागू कर रही है।

कतर से वार्ता के बाद दिया प्रस्ताव, अब ट्रम्प पर नजर

ईरान ने 2 दिन में होर्मुज खोलने का दिया ऑफर

तेहरान, आरएनएन। ईरान ने एक बार फिर होर्मुज खोलने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है। ईरान और कतर ने वार्ता के जरिए अमेरिका को शर्तें मानकर दो दिन के भीतर होर्मुज खोलने का ऑफर दिया है।

अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बरकरार

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि कतरी मध्यस्थों के साथ बातचीत के बाद तय किया गया है कि अगर अमेरिका तेहरान की शर्तें मान लेता है तो दो दिन में होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रपोजल पर डोनाल्ड ट्रंप को फैसला लेना है। अल जजीरा के मुताबिक, अराघची ने बताया कि कतर के साथ चर्चा के बाद होर्मुज खोलने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा को पांच से घटाकर दो दिन किया गया है।

ईरानी वार्ताकारों ने शनिवार को दोहा में कतरी मध्यस्थों के साथ बातचीत की है। कतर में यह बातचीत शुक्रवार को तेहरान में ईरानी और कतरी प्रतिनिधियों के बीच 12 घंटे की चर्चा के बाद हुई है।

क्या हैं ईरान की शर्तें

तेहरान की मांगों के बारे में बताते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इनमें इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की संख्या कम करना, तेल छूट (ऑयल वेवर्स) को बहाल करना और ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करना शामिल है। हम तेल छूट की बहाली और अपने सभी फ्रीज किए गए फंड को जारी करने की मांग करते हैं, जिसमें कतर में मौजूद फंड भी शामिल हैं। अराघची ने आगे कहा कि हमारी शर्तों में इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना और क्षेत्र में अमेरिकी बलों की संख्या कम करना शामिल है। उन्होंने कहा, ईरान चाहता है कि होर्मुज में उन शिपिंग मार्गों को मान्यता दी जाए, जिन पर तेहरान ने ओमान के साथ चर्चा की थी। साथ ही अन्य मार्गों को बंद कर दिया जाए। हमारी शर्तों के अनुसार होर्मुज को फिर से खोलने से और वाशिंगटन से लंबित मुद्दों पर वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ईरान का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता के संभावित ढांचे को लेकर राजनयिक स्तर पर चर्चा जारी है।

एनएसए डोभाल वियतनाम पहुंचे



हनोई, आरएनएन। एनएसए अजीत डोभाल रविवार को एक आधिकारिक यात्रा पर वियतनाम पहुंचे और इस दौरान वह द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए देश के नेतृत्व के साथ बात करेंगे। हनोई में भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट में कहा कि डोभाल की यह यात्रा भारत-वियतनाम उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के अनुरूप है। मई में, भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को 'उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुंचाया और 2030 तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर का वार्षिक व्यापार लक्ष्य तय किया।

आर्मेनिया संसद में सेक्स मंत्रालय को लेकर चले लात-घूंसे, सदन में हंगामा

● येरावन

अर्मेनिया की संसद में एक बार फिर झगड़ा हुआ और एक महीने में यह तीसरी बार है। वैसे तो भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों के कथित गबन के आरोपों को लेकर यहां पहले से बवाल हो रहा है। लेकिन इस बार झगड़े की वजहों में सेक्स मिनिस्ट्री को लेकर किया गया एक पुराना कमेंट भी शामिल है।

कुछ महीनों पहले विपक्षी पार्टी से जुड़े एक शख्स ने सेक्स मिनिस्ट्री को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर अब सदन में हंगामा हो गया और विवाद लात-घूंसों तक पहुंच गया।



सेक्स मिनिस्ट्री को लेकर विवाद क्या है : दरअसल, सेक्स मिनिस्ट्री को लेकर यह विवाद किसी आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव या संसद में पेश किए गए विधेयक से नहीं जुड़ा है। इसका कनेक्शन जनवरी में जारी हुए एक पॉडकास्ट से है। उस वक्त आर्मेनिया में विपक्षी पार्टी स्ट्रॉन्ग आर्मेनिया से जुड़े सरगिस करापेत्यान ने एक पॉडकास्ट में देश की जनसंख्या से जुड़ी समस्या पर बातचीत की थी। पॉडकास्ट में एक अन्य प्रतिभागी ने मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का काल्पनिक नाम सुझाया। इस पर सरगिस करापेत्यान ने कहा कि सेक्स के बिना जनसांख्यिकीय समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसी बातचीत में मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाने का सुझाव आया।

नेपाल में भारी बर्फबारी, ट्रेकिंग के दौरान छह भारतीय पर्यटक लापता

● काठमांडू

नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। सभी पर्यटक नेपाल की सबसे गहरी झीलों में से एक शे-फोक्सुंडो की ट्रेकिंग पर निकले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पर्यटक डोल्पो बुद्ध ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर चार और आठ से झील की ओर जा रहे थे। उन्हें आखिरी बार शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नपा के वार्ड चार और आठ के बीच स्थित नुमला पास और बागला पास के इलाकों में देखा गया था। गाइडों को आशंका है कि चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई भारी बर्फबारी से पर्यटक पहाड़ों में फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पर्यटकों ने यात्रा जारी रखी।

नागपुर के आठ ज्वेलर्स को रंगदारी की धमकी

लॉरेंस गैंग के नाम से प्रत्येक से मांगे 10 लाख

● नागपुर

नागपुर में रविवार को रंगदारी की धमकी से ज्वेलर्स में चिंता बढ़ गई है। कथित तौर पर आठ सर्राफा कारोबारियों को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे पत्र भेजे हैं। प्रत्येक से 10 लाख की मांग की है। डाक के जरिए भेजे गए इन पत्रों में कथित तौर पर कारोबारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। रकम नहीं देने पर उन्हें गोली मारने या जान से खत्म करने की धमकी दी गई है। कहा-जैसे टाइगर श्रॉफ को मारा, वैसे ही मारेंगे। तीन से पांच दिन में रकम देने का अल्टीमेटम- रिपोर्टों के अनुसार, धमकी भरे पत्रों में कारोबारियों को अलग-अलग समयसीमा दी गई है। कुछ से तीन दिन के भीतर, जबकि अन्य से पांच दिन में रकम जुटाने को कहा गया है।

ब्रीफ न्यूज

नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया

प्योंगयांग, आरएनएन। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। देश के रक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थानों ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाने स्टैंडर्ड टाइप-2 क्लस्टर बम वॉरहेड का अहम टेस्ट किया। यह टेस्ट 31 अक्टूबर को हुआ था। जनरल किम जोंग-सिक ने इस टेस्ट की निगरानी की। इस वॉरहेड ने अधिकतम घनत्व पर 12 से 13 हेक्टेयर के लक्ष्य क्षेत्र को नष्ट करने की क्षमता दिखाई। यह परीक्षण युद्ध की परिस्थितियों में वॉरहेड की अनुकूलन क्षमता और उसकी विनाश शक्ति को जांचने के लिए किया गया था।

कबाड़ी से खरीदी मामूली चीज निकली 1956 की दुर्लभ मशाल

स्टाकहोम, आरएनएन। स्वीडन की एक महिला ने कबाड़ी बाजार से बेहद सस्ते दाम पर एक एल्यूमिनीयम की मशाल खरीदी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ लगा यह सामान इतिहास का एक दुर्लभ हिस्सा है। दरअसल, यह 1956 के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार एक खास मशाल थी। जब इसे नीलामी के लिए रखा गया तो इसकी कीमत 1.31 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई। इस मशाल को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि दुनिया में आज इसके 10 से भी कम नमूने मौजूद हैं।

एक्स-59 विमान ने पहली वर्षगांठ पर यूएस के ऊपर भरी उड़ान

वाशिंगटन, आरएनएन। नासा के बेहद पतले और नुकीले एक्स-59 सुपरसोनिक प्रायोगिक विमान ने पहली उड़ान की पहली वर्षगांठ पर पूरे अमेरिका के ऊपर से उड़ान भरी। यह विमान कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर की यात्रा पर निकला था। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए, जो वायरल हो गए। नासा प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने वीडियो की सराहना करते हुए विमान के कैनेडी सेंटर पहुंचने की पुष्टि की। विमान के साथ एक एफ-15, एक एफ/ए18 और एक गल्फस्ट्रीम सी-20 विमान एस्कॉर्ट के रूप में चल रहे थे।

पायलट प्रोजेक्ट — रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर केसर के फूल खिलना शुरू हुए, बंजर भूमि को लेकर प्रयोग रहा सफल

लद्दाख में खिले केसर के फूल, खेती के खुले नए रास्ते

● लेह

केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के काफी ऊंचाई वाले जगहों पर केसर की खेती में एक नई सफलता हासिल हुई है। सामान्य तौर पर फूल खिलने में लगने वाले दो महीने के समय के विपरीत यहां रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर केसर के फूल खिलना शुरू हो गए हैं।

लेह में हाल ही में बंजर भूमि को लेकर एक प्रयोग किया गया था और इसमें जमीन की कुछ देखभाल के बाद प्रयोग के तौर पर केसर की खेती शुरू की गयी। अब इस खेती ने पहले ही महीने रंग लाना शुरू कर दिया है।



लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केसर की फसल का निरीक्षण किया।



औसतन 20 से 25 फूल रोजाना खिल रहे, रविवार सुबह खिले 72 फूल

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में औसतन 20 से 25 फूल रोजाना खिल रहे हैं, जबकि रविवार सुबह 72 फूल खिले। केवल चार दिनों के भीतर ही लगभग 22 ग्राम शुद्ध केसर एकत्र किया जा चुका है। उपराज्यपाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता में अहम योगदान देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कृषि विभाग, समर्पित वैज्ञानिकों और मैदानी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है।

इसे लद्दाख की पर्यावरण सहनशीलता और क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली खेती की असीम और अप्रयुक्त संभावनाओं का एक बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। इस सफलता से लद्दाख में कृषि, कृषि-आधारित उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे और एक मजबूत, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था का रास्ता खुलेगा।

संजय गुप्ता की अंतिम विदाई

बेटी ने पैपराजी का किया अपमान

मुम्बई, आरएनए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को शनिवार को एक झटका तब लगा जब फिल्ममेकर संजय गुप्ता का अचानक निधन हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ था, लेकिन उस बीच उनकी बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ।



बीते दिन संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार के बाद पैपराजी ने डायरेक्टर की बेटी दलाई गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका दावा है कि वो पैप्स को आपत्तिजनक इशारे कर रही थीं। वीडियो में वो उन्हें मिडल फिंगर दिखाकर हंस रही थीं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो संजय गुप्ता की बेटी ही थीं, क्योंकि तब उन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। वीडियो में एक लड़की कार की आगे वाली सीट पर बैठी नजर आ रही है। उसने हुडी से अपना चेहरा ढक रखा है।

वीडियो में लड़की फोटोग्राफर्स की तरफ देखकर हंसती हुई नजर आती है और फिर उन्हें मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसे आपत्तिजनक इशारा माना जाता है। कार चला रहा शख्स उसे रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लड़की फिर भी ऐसा करती रहती है। पीछे बैठा एक शख्स भी उसे रोकने की कोशिश करता नजर आता है।

आज का इतिहास

- **1774:** अंग्रेज अधिकारी कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया राबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या की।
- **1834:** एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था जिसे वहां अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **1835:** अमेरिका के मूल निवासियों के विभिन्न गुटों के बीच फ्लोरिडा के ओसिओला में दूसरा सेमीनोले युद्ध शुरू हुआ। यह लड़ाई फ्लोरिडा युद्ध के नाम से भी मशहूर है।
- **1841:** अकबर खान ने अफगानिस्तान में शाह शुजा के खिलाफ विद्रोह किया,जिसमें उसे सफलता मिली।
- **1852:** फ्रेंकलिन पियर्स अमेरिका के राष्ट्रपति बने।

जयपुर-गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार का साइलेंट-अटैक से निधन

बेटे ने मुखाग्नि दी; गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा से जुड़े थे



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी (77) का रविवार को निधन हो गया। दोपहर करीब 12 बजे साइलेंट अटैक आने के बाद उन्हें दुर्लभजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जलमहल के सामने समाज बाड़ी में शाम को महंत अंजन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे मानस गोस्वामी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले, उनकी अंतिम यात्रा सुभाष चौक क्षेत्र में पानों के दरीबे स्थित हवेली से रवाना हुई थी। अंतिम यात्रा में जयपुर के प्रमुख मंदिरों के महंत और गोविंददेवजी मंदिर से जुड़े लोग मौजूद रहे। महंत अंजन कुमार गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा से जुड़े थे। वे मंदिर के महंत होने के साथ इसके एकमात्र सेवाधिकारी और ट्रस्टी भी थे।

महंत को बेटे ने दी मुखाग्नि

महंत अंजन कुमार गोस्वामी का जलमहल के सामने समाज बाड़ी में पंचतत्व में विलीन हुए।
बेटे मानस गोस्वामी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मंदिर से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। समाज बाड़ी गोविंददेवजी के गोस्वामी परिवार के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थल है।

महंत की अंतिम यात्रा रवाना

महंत अंजन कुमार गोस्वामी की अंतिम यात्रा शाम करीब 4:15 बजे सुभाष चौक क्षेत्र में पानों का दरीबा स्थित उनकी हवेली से जलमहल के सामने स्थित समाज बाड़ी के लिए रवाना हुई। अंतिम यात्रा में जयपुर के प्रमुख मंदिरों के महंत भी शामिल हुए। समाज के लोगों और भक्तों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। समाज बाड़ी में गोस्वामी समाज के निर्धारित स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

गोविंददेवजी के विग्रह को वृंदावन से लाए थे

गोविंददेवजी मंदिर की धार्मिक परंपरा चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामी से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार, वृंदावन में भगवान गोविंददेवजी के विग्रह की खोज रूप गोस्वामी ने की थी। बाद में मुगल शासन के दौरान विग्रह को वृंदावन से आमेर लाया गया। जयपुर की स्थापना के बाद सिटी पैलेस परिसर स्थित जय निवास उद्यान में स्थापित किया गया। जयपुर के पूर्व शासक भगवान गोविंद देवजी को अपना राजा मानते थे।

54 साल पहले मंदिर ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था मंदिर

गोविंद देवजी मंदिर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग में 20 सितंबर 1972 को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था। मंदिर की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। अंजन कुमार गोस्वामी के बेटे मानस कुमार गोस्वामी भी शिक्षा पूरी करने के बाद मंदिर की सेवा से जुड़ गए।

पिता के बाद संभाली थी मंदिर की जिम्मेदारी

महंत अंजन कुमार गोस्वामी स्वर्गीय प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी के बड़े पुत्र थे। उनके पिता ने मंदिर की सेवा और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिता के बाद अंजन कुमार गोस्वामी ने मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी संभाली और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अंजन कुमार के कार्यकाल में मंदिर ने वर्तमान स्वरूप और भव्यता हासिल की।

राजस्थान के 7 पुलिस-अफसरों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक

6 आईपीएस और एक आरपीएस अधिकारी का चयन,सभी को बेस्ट अनुसंधान श्रेणी में मिलेगा सम्मान

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। अपराधों की सटीक, निष्पक्ष और गहन जांच में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान के सात पुलिस अधिकारियों को साल-2026 का केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक मिलेगा। इनमें राजस्थान कैडर के 6 आईपीएस और एक आरपीएस अधिकारी शामिल हैं। सभी का चयन बेस्ट अनुसंधान श्रेणी में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से घोषित इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए देशभर के कुल 490 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें 26 राज्यों के पुलिस बलों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और विभिन्न केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारी भी शामिल हैं। राजस्थान में तैनात केंद्रीय एजेंसियों के कुछ कार्मिकों को भी इस सम्मान के लिए चुना गया है।

तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे पदक

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। स्पेशल ऑपरेशन श्रेणी में अर्धसैनिक बलों के 358 कार्मिकों, बेस्ट अनुसंधान श्रेणी में केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्यों के पुलिस बलों के 123 अधिकारियों व फॉरेंसिक साइंस श्रेणी में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के 9 विशेषज्ञों का चयन हुआ है। चयनित कार्मिकों में सीआरपीएफ, असम राइफल्स, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, सीबीआईएसी-डीआरआई और सीएफएसएल से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

हर साल 31 अक्टूबर को होती है घोषणा

यह पदक पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों और फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य तथा उच्च पेशेवर मानकों के लिए दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पुरस्कार की अधिसूचना 1 फरवरी 2024 को जारी की थी। इसके तहत हर साल सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को पदक पाने वालों के नाम घोषित किए जाते हैं।

जयपुर में खादी में सजे फैशन के नए ट्रेंड्सः विंटर और वेडिंग कलेक्शंस किए शोकेस; रैंप पर दिखा परंपरा-आधुनिकता का संगम

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। खादी के कपड़ों में जब आधुनिक डिजाइन, फैशन और शिल्प का संगम हुआ तो रैंप नए रंगों से सराबोर हो उठा। कहीं खादी के प्राकृतिक स्वरूप को आधुनिक परिधानों में ढाला गया तो कहीं पारंपरिक शिल्प के साथ फ्यूजन डिजाइन ने फैशन के नए ट्रेंड्स पेश किए। विंटर और वेडिंग कलेक्शन के जरिए डिजाइनर्स ने खादी को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (एफडीसीआर) और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से रविवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित 'ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ' फैशन शो आयोजित हुआ।

एफडीसीआर की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से 'डिजाइन ऑफ द ईयर-2026' का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में फैशन वर्ल्ड के डिजाइनर्स, विशेषज्ञों और फैशन प्रेमियों ने हिस्सा लिया।



'सूत' में खादी के साथ दिखा फ्यूजन का अंदाज

खादी राजस्थान की प्रस्तुति में संजय अग्रवाल का 'सूत' कलेक्शन रैंप पर आया। इस प्रस्तुति में खादी को नए फैशन ट्रेंड्स के साथ जोड़कर पेश किया गया। खादी के पारंपरिक स्वरूप के साथ फ्यूजन डिजाइन का प्रयोग इसकी खासियत रहा। खादी कारीगरों की प्रस्तुति ने इस फैशन शोकेस को पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से भी जोड़ा।

खादी के साथ फ्यूजन और आधुनिक डिजाइन का प्रयोग

'ग्रासरूट-द आर्ट ऑफ अर्थ' की थीम में धरती, प्रकृति, पारंपरिक शिल्प और खादी के मूल स्वरूप को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ने का प्रयास नजर आया। खादी की प्राकृतिक बनावट और उसकी पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए डिजाइनर्स ने इसे नए डिजाइन और समकालीन फैशन ट्रेंड्स के साथ प्रस्तुत किया। फैशन शोकेस में खादी के परिधानों के साथ विंटर और वेडिंग कलेक्शन भी प्रदर्शित किए गए।

उभरती प्रतिभाओं ने दिखाई डिजाइन की नई सोच

कार्यक्रम की शुरुआत लुमोरा एक्स की प्रस्तुति 'जेन नेक्स्ट डिजाइनर्स' से हुई। इसमें पोद्दार कॉलेज ऑफ डिजाइन, कोड बाय वीजीयू और एमिटी स्कूल ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के डिजाइनर्स के कलेक्शन शोकेस किए गए। उभरते डिजाइनर्स ने अपने परिधानों के जरिए फैशन की नई सोच और रचनात्मक प्रयोगों को सामने रखा। उनके कलेक्शन में आधुनिक डिजाइन दृष्टि और बदलते फैशन ट्रेंड्स की झलक देखने को मिली।

डिजाइनर्स को अवॉर्ड देकर किया प्रोत्साहित

अराय सिलाई मशीन की ओर से 'डॉटी डिजाइनर्स अवॉर्ड्स सेरेमनी' आयोजित की गई। इसमें डिजाइनर्स को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद हेयरजॉय की प्रस्तुति में रचना खंडेलवाल के 'छोरिताई' और गुरमीत सिंह कपूर के 'जी-क्लास' कलेक्शन शोकेस किए गए। दोनों कलेक्शन के जरिए डिजाइनर्स ने अपने अलग-अलग फैशन दृष्टिकोण और परिधान डिजाइन को प्रस्तुत किया।

भाटी बोले-EWS पर 7 साल बाद भी नियम सरल नहीं

विधायक ने कहा- पिता-पति की आय के आधार पर महिलाओं के आवेदन हो रहे रिजेक्ट

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा- सात साल से EWS आरक्षण में सरलीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका खमियाजा खासतौर पर ग्रामीण परिवेश के युवाओं और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है।

जयपुर में रविवार को बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने यह कहा। भाटी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण में सरलीकरण की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। भाटी ने बताया- कई मामलों में पिता और पति की आय के आधार पर महिलाओं के आवेदन निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में नियमों को सरल बनाने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को भी आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद कर श्रृङ्खल आरक्षण के नियमों में बदलाव की मांग उठाई।

मीडिया से बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी ने कहा- EWS आरक्षण में सरलीकरण की मांग वर्ष 2019 से उठाई जा रही है। पिछले सात साल में अलग-अलग जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य स्तर पर EWS प्रमाण पत्र के नियमों में कुछ राहत दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर अब भी कई शर्तें लागू हैं।

भाटी ने कहा- इन शर्तों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई वास्तविक जरूरतमंद युवा आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया और पात्रता के नियमों में सरलीकरण करना चाहिए।

उन्होंने कहा- EWS आरक्षण का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए जमीन से जुड़ी शर्तों में राहत और महिलाओं को आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और युवाओं ने भी मंच से EWS नियमों को सरल बनाने की मांग उठाई।

डबल इंजन सरकार को युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए

भाटी ने कहा- राजस्थान और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। ऐसे में अब केंद्र सरकार को EWS आरक्षण के नियमों में बदलाव कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को राहत देनी चाहिए।



उन्होंने कहा- EWS आरक्षण में कई ऐसी शर्तें और बाधाएं हैं, जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और जरूरतमंद परिवारों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय करना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार इस मांग पर विचार करेगी।

महिलाओं को आयु में मिले छूट, जमीन की शर्त में हो बदलाव

भाटी ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा- सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन EWS प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े नियमों में महिलाओं को भी राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा- राजस्थान में राज्य स्तर पर EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमीन संबंधी शर्तों में छूट दी गई है। इसके साथ ही आयु सीमा में भी राहत का प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्र सरकार के स्तर पर प्रमाण पत्र बनवाने में अब भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं।

युवाओं के वोट से सत्ता में आई सरकार, अब उनकी मांगों पर फैसला करे

शिव विधायक भाटी ने कहा- प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में अनारक्षित वर्ग के युवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवाओं ने सरकार से उम्मीदें लगाकर समर्थन दिया है। ऐसे में सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और श्रृङ्खल आरक्षण में सरलीकरण के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए नियमों में मौजूद व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना जरूरी है।

कांग्रेस की रैली पर बोले- सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी

दिल्ली में कांग्रेस की रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा- लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा-जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। लोगों को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष करते रहना चाहिए। भाटी ने कहा कि EWS सरलीकरण की मांग भी इसी तरह लगातार उठाई जा रही है। जब तक नियमों में जरूरी बदलाव नहीं होंगे, तब तक वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने भी EWS आरक्षण में सरलीकरण की मांग को प्रमुखता से उठाया। भाटी ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है।

स्टेज पर चढ़ा स्टूडेंट तो चीख पड़ीं सुनंदा शर्मा

कॉन्सर्ट के बीच हुआ हंगामा, सुरक्षाकर्मियों ने संभाली स्थिति; सलीम-सुलेमान की भी लाइव परफॉर्मेंस



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। जयपुर के 2 कॉलेजों में शनिवार रात बॉलीवुड और पंजाबी संगीत की धूम रही। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने आगरा रोड स्थित आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइव परफॉर्मेंस दी। इस दौरान एक स्टूडेंट सिक्योरिटी तोड़कर मंच पर आ गया, जिससे सुनंदा शर्मा डर गई और चीख पड़ी।

वहीं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में सिंगर सलीम-सुलेमान ने चक दे इंडिया, ओ रे पिया', 'आजा नचले', 'हौले हौले', 'ऐनवयी ऐनवयी' और 'शुक्रान अल्लाह' जैसे गानों पर परफॉर्म किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने भी सिंगर के साथ सुर में सुर मिलाए।

कॉन्सर्ट के बीच स्टेज पर चढ़ा स्टूडेंट

आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में सुनंदा शर्मा की प्रस्तुति के दौरान अचानक एक स्टूडेंट स्टेज पर चढ़ गया। उसे अचानक सामने देखकर सुनंदा घबरा गईं और उनके मुंह से चीख निकल गई।

मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली। घटना के बाद कुछ देर के लिए कॉन्सर्ट रोकना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद सुनंदा फिर मंच पर लौटीं और पूरे जोश के साथ परफॉर्मेंस दी। इस दौरान सुनंदा शर्मा ने अपने चर्चित गीत 'जानी तेरा ना', 'मम्मी नू पसंद', 'सैंडल', 'पागल नहीं होना', 'चोरी चोरी' और 'तेरे नाल नचना' को लाइव परफॉर्म किया।

एमएनआईटी में 'चक दे इंडिया' पर थिरके स्टूडेंट्स

एमएनआईटी में सलीम-सुलेमान की जोड़ी ने अपने ऊर्जावान अंदाज से माहौल को संगीत समारोह में बदल दिया। दोनों ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों के साथ विद्यार्थियों को झूमने पर मजबूर किया।

प्रस्तुति के दौरान सलीम मर्चेंट हाथ में तिरंगा लेकर 'चक दे इंडिया' गाते नजर आए। गीत की धुन और तिरंगे के साथ उनकी प्रस्तुति पर स्टूडेंट्स ने जोरदार उत्साह दिखाया।

रात 12 बजे अचानक उतरी सफाईकर्मियों की 'फौज'

पुराने शहर की हर गली में घूमे मेयर-कमिश्नर, झाड़ू लगाई; अब सफाई के लिए होगी 'दौड़'

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। दिवाली से पहले राजधानी जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने शनिवार रात परकोटे में विशेष सफाई अभियान चलाया। 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0' के तहत रात 12 बजे से पूरी रात परकोटे के प्रमुख बाजार और अंदरूनी गलियों में सफाई की गई।

अभियान में नगर निगम मेयर सुनील कोठारी और कमिश्नर ओम कसेरा ने भी मोर्चा संभाला। करीब ढाई हजार सफाई कर्मचारियों और 1000 संसाधनों की मदद से परकोटे के बाजार, सड़कों और गलियों से कचरा हटाया गया।

मेयर सुनील कोठारी ने खुद झाड़ू लेकर सफाई की। दरअसल, दिवाली पर बाजारों और घरों में साफ-सफाई के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ जाती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने इस बार त्योहार से पहले विशेष सफाई अभियान चलाने का फैसला किया।

घर की तरह शहर की भी करें सफाई

मेयर सुनील कोठारी ने कहा- दीपोत्सव पर जिस तरह हर व्यक्ति अपने घर की विशेष सफाई करता है, उसी तरह नगर निगम शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रहा है। इसके लिए करीब 2 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों और संसाधनों को लगाया गया।



शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर पूछे गए सवाल पर मेयर ने कहा- ये दोनों गंभीर मुद्दे हैं।

इनके समाधान के लिए नगर निगम को अपनी कमियों को दूर करने के साथ ही आमजन का सहयोग भी बढ़ाना होगा। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा- शहर को स्वच्छ बनाने के लिए वार्ड स्तर पर युवाओं को जोड़कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

दिन में ट्रैफिक, इसलिए रात में सफाई अभियान

नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया- कुछ महीने पहले नगर निगम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया था। इसके तहत रातों-रात शहर के प्रमुख हिस्सों की विशेष सफाई की गई थी। उसी कड़ी में अब ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0 आयोजित किया है।

उन्होंने कहा- इस बार अतिरिक्त कर्मचारी और संसाधन लगाकर परकोटे में रातभर सफाई कराई जा रही है। दिन में बाजारों में ट्रैफिक और आमजन की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने से लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए रात का समय चुना गया, ताकि आमजन की आवाजाही प्रभावित किए बिना दिवाली के दौरान निकलने वाले अतिरिक्त कचरे को हटाया जा सके।

सड़क पर कचरा नहीं फेंकें, निगम की गाड़ी में ही डालें

नगर निगम कमिश्नर ने कहा- नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन इसमें आमजन की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से बचना चाहिए। घरों का कचरा नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी में ही डालना चाहिए।

उन्होंने कहा- केवल नगर निगम के प्रयासों से शहर को लंबे समय तक स्वच्छ नहीं रखा जा सकता। जब तक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सफाई व्यवस्था में स्थाई सुधार मुश्किल है। शहर को साफ रखने के लिए निगम और आमजन को मिलकर काम करना होगा।

अब स्वच्छता मैराथन की तैयारी

निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया- आमजन की भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद नगर निगम ने 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान आयोजित किया था। अब दीपोत्सव से पहले ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0 चलाया गया। जल्द ही स्वच्छता मैराथन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा- इन अभियानों का उद्देश्य केवल कुछ दिनों तक सफाई करना नहीं, बल्कि शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है।

नगर निगम चला रहा अलग-अलग अभियान

जयपुर नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग अभियान चला रहा है। 'रंग दे गुलाबी', स्वच्छता मैराथन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप जैसे अभियानों के जरिए सफाई के साथ आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रंग दे गुलाबी और ऑपरेशन क्लीन स्वीप का दूसरा चरण पूरा हो चुका है। अब स्वच्छता मैराथन की तैयारी है। नगर निगम का प्रयास है कि दिवाली से पहले शहर के बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरे को हटाकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादक: रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिस: 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडी: tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइट: www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।